



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

#### PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2015/ज्येष्ठ 20, 1937

No. 158]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2015/JYAISTHA 20, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

(अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 10 जून, 2015

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन सी के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णयक समीक्षा

सं.15/10/2014-डीजीएडी : समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

#### क. मामले की पृष्ठभूमि

2. समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए; भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में उपरोक्त नियमावली के अंतर्गत नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने मूल जांच में चीन जन.गण. एवं जापान के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "विटामिन सी" (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निर्णयिक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण करने की सिफारिश दिनांक 25 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या 10/1/97-एडीडी के तहत की थी और केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या 53/98-सीसी के तहत निर्णयिक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया था।

3. यतः, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 24 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या 53/98-सीयूएस के तहत अधिरोपित अंतिम पाटनरोधी शुल्क की निर्णयक समीक्षा जांच आयोजित की और यह जांच की कि क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना अधिक है और संबद्ध वस्तु के चीन जन.गण. ये संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क में विस्तार करने की सिफारिश दिनांक 31 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/4/2002-डीजीएडी के तहत की। केंद्रीय सरकार द्वारा इस शुल्क में विस्तार दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 159/2003-सीमाशुल्क के तहत की है।

4. यतः, प्राधिकारी ने द्वितीय निर्णयक समीक्षा जांच का आयोजन किया और दिनांक 21 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या 15/16/2008 के तहत पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश की। केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 67/2009-सीमाशुल्क के तहत पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया।

5. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अधिरोपित की गई पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले ही प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगी।

6. और, उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, प्राधिकारी को, उक्त समाप्त की तारीख से पहले एक युक्तियुक्त समयावधि के अंदर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से एक विधिवत साक्षात्कृति आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या शुल्क को समाप्त कर देने से पाअन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

7. और यतः, उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले वजाज हेल्थकेयर लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात आवेदक अथवा याचिकाकर्ता कहा गया है) ने प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्षात्कृति आवेदनपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 16 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 67/2009-सीमाशुल्क के तहत अधिरोपित प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने का अनुरोध किया। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि चीन जन.गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है क्योंकि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क का स्वरूप एवं उसकी प्रमात्रा पर्याप्त नहीं है। आवेदक ने पुनः यह तर्क दिया है कि संबद्ध वस्तु के विपरीत इस साधन को समाप्त कर देने से यह पूर्ण संभावना है कि उसके परिणामस्वरूप पाटन की निरंतरता बने रहने तथा घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क के साथ का प्रतिसंहरण कर देने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को तीव्रीकृत क्षति होगी और इसलिए शुल्क के अगले पांच वर्षों तक बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

8. यह आवेदन पत्र भारत में संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की ओर से वजाज हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त, अमोली आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रेकन फार्मार्किम प्राइवेट लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन इस संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता है और इसलिए, वह पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है और वह नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

9. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा दिए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर यह विचार करते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णयक समीक्षा की कार्रवाई शुरू करना पाटन को समाप्त करने के लिए ऐसे शुल्कों का सतत अधिरोपण करने की जरूरत की जांच करने के लिए आवश्यक है और क्या शुल्क को हटा लिए जाने अथवा उसमें परिवर्तन करने अथवा दोनों करेन पर क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

10. पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए प्रथम दृष्टया सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा की जरूरत के लिए साक्षात्कृति से स्वयं संतुष्ट होकर प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर प्रभावी शुल्क के सतत अधिरोपण की जरूरत की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहेगी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार 11 जून, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/10/2014-डीजीएडी के तहत निर्णयक समीक्षा की शुरूआत करते हैं।

11. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता केंद्रीय सरकार दिनांक 23.07.2014 की अधिसूचना संख्या 33/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत 15 जून, 2015 तक, उस दिन को शामिल करते हुए, बढ़ा दी गई है।

12. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पूर्व जांच के सभी पहलू कवर होंगे।

#### **ख. प्रक्रिया**

13. इस जांच में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया :

(i) इस जांच की शुरूआत के संबंध में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के राजदूतावास को नियमानुसार सूचित किया गया।

(ii) प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय पाठ की प्रतियों तक नियमानुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों और राजदूतावास को तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पहुंच उपलब्ध कराई।

(iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की प्रतियां संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अग्रेपित किए और उन्हें नियमों के अंतर्गत उसके चालीस दिनों के अंतर्गत लिखित रूप में उपलब्ध कराने का अवसर प्रदान किया :

- (क) आबोजी ओएशियर बायो-टेक कंपनी लिमिटेड
- (ख) दि टीएनएन डेवलपमेंट लिमिटेड
- (ग) निंग्बो फार्मेकोस इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
- (घ) ज्ञेन्ज़ोऊ बाओकारो फार्मास्युटिकल एंड हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
- (ङ) डालिआन साइनोबायो कैमिस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- (च) किंवङ्गडाओ डेकान ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

(iv) संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों में से किसी ने भी कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया।

(v) चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण, चीन जन.गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों और चीन जन.गण. के राजदूतावास को एक बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी) प्रश्नावली भी इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराएं। यद्यपि, इस जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ चीन में सामान्य मूल्य पर विचार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, विधिवत समायोजित के आधार पर किया गया, तथापि प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को यह सूचित किया कि उनका आवेदक के दावे की जांच यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में करने का प्रस्ताव है। इसलिए चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों/निर्यातकों से यह अनुरोध किया गया कि वे यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराएं जिससे प्राधिकारी इस तथ्य पर विचार करने में सक्षम हो सके कि क्या उस देश के सहयोगकर्ता निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तथापि, चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से इस संबंध में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(vi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं/उपभोक्ता एसोसिएशनों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की गई और उन्हें यह सलाह दी गई कि वे नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत अपने विचारों से प्राधिकारी को लिखित रूप में अवगत कराएं।

- (क) ग्लैब्सो स्मिथलाइन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
- (ख) फिजर लिमिटेड
- (ग) ग्लोबल एक्सिम
- (घ) एंग्लो फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड
- (ङ) पीरामल हेल्थकेयर लिमिटेड
- (च) रेनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड
- (छ) डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड
- (ज) मेयर आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- (झ) वोवान्टिस लैबोरेटरीज
- (झ) जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड
- (ट) पारले एंग्रो प्राइवेट लिमिटेड

- (vii) उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित आयातकों ने आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया :
- (क) एबाट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई
  - (ख) फिजर लिमिटेड, मुंबई
- (viii) निम्नलिखित आयातकों/एसोसिएशनों ने जांच शुरूआत के पश्चात अपना विधिक प्रस्तुतिकरण किया :
- (क) पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुंबई
  - (ख) प्राइड ड्रग्स एंड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद
  - (ग) एबाट हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
  - (घ) ओपीपीआई (आर्गनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल प्रोड्युसर्स आफ इंडिया)
- (ix) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 (15 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2010 - मार्च, 2011, अप्रैल 2011 – मार्च 2012, अप्रैल 2012 – मार्च, 2013 तथा जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा।
- (x) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया कि वह भारत में, जांच की अवधि सहित, पिछ्ले तीन वर्षों में हुए संबद्ध वस्तु के आयातों का विवरण प्रदान कराए। डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदेवार सूचना को इस जांच के लिए अपनाया गया।
- (xi) उन निर्यातकों, उत्पादकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने प्राधिकारी को न तो कोई प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रेषित की, उन्हें प्राधिकारी द्वारा असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।
- (xii) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ नियम के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए एक खुली फाइल में रखा गया।
- (xiii) प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-III में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप यथासंभव सीमा तक की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (xiv) नियमानुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह अवसर भी प्रदान किया कि दिनांक 6 मई, 2015 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से अभिव्यक्त करे। इस मौखिक सुनवाई में विचार व्यक्त करने वाले पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें।
- (xv) जांच की कार्रवाई के दौरान तथा मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों इस जांच में यथासंभव सीमा तक समाधान कर दिया गया है।
- (xvi) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों एवं सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक और स्थल सत्यापन किया गया।
- (xvii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया और उसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां कहीं संभव हुआ वहां, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करें।
- (xviii) जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही की है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा इस जांच को भारी अवरोध उत्पन्न किया है, वहां प्राधिकारी ने उक्त जांच "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर की है तथा इन पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना।
- (xix) इस जांच के लिए अनिवार्य समझे गए तथ्यों/आधारों से युक्त एक प्रकटन विवरण का प्रकटन जो अंतिम जांच परिणाम का आधार है सभी ज्ञात हितबद्ध को दिनांक 02.06.2015 को किया गया। प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरणों पर इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में संगत पाई गई सीमा तक विचार किया गया।

(xx) इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में \*\*\* हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व कर रहा है तथा प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है।

(xxi) जांच की अवधि के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डालर = 58.05/-रुपए है

#### **ग. विचाराधीन उत्पाद एवं "समान वस्तु"**

##### **घरेलू उद्योग के विचार**

14. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं :

(क) इस जांच में विचाराधीन उत्पाद विटामिन सी, अपने सभी स्वरूपों एवं अवकलजों में है।

(ख) विटामिन सी को मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या 867 के अंतर्गत यथावर्णित इसके विभिन्न समानार्थियों के रूप में भी जाना जाता है जैसे एस्कार्बिक एसिड, एल-जाइलोएस्कार्बिक एसिड, 3 ओक्सो एल - गुलोफुरानोलैक्टोन (एनाल फार्म), एल-3 - कीटोश्रियोहेक्सरोनिक एसिड लैक्टोन आदि।

(ग) विटामिन सी का फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा प्रमुखतः विभिन्न औषधियों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तथापि, इस उत्पाद का गैर-फार्मास्युटिकल उद्योग में भी भारी प्रयोग होता है।

(घ) विटामिन सी एक आर्थिक रसायन है। इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 2936.27 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया जाता है। अध्याय 29 का संपूर्ण वर्गीकरण, जहां तक इसका संबंध इस उत्पाद के आयातों से है, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार 29362700 है।

(ङ) इस विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में इस उत्पाद का दायरा था।

##### **हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

15. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई भी प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

##### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

16. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित विटामिन सी, अपने सभी स्वरूपों एवं अवकलजों में, है। विटामिन सी को मर्क इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या 867 के अंतर्गत यथावर्णित इसके विभिन्न समानार्थियों के रूप में भी जाना जाता है जैसे एस्कार्बिक एसिड, एल-जाइलोएस्कार्बिक एसिड, 3 ओक्सो एल - गुलोफुरानोलैक्टोन (एनाल फार्म), एल-3 - कीटोश्रियोहेक्सरोनिक एसिड लैक्टोन आदि। विटामिन सी का फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा प्रमुखतः विभिन्न औषधियों का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तथापि, इस उत्पाद का गैर-फार्मास्युटिकल उद्योग में भी भारी प्रयोग होता है। इसे सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 29362700 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

17. प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयातित वस्तु के समान उत्पाद है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक अभिलक्षणों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देश से आयातित वस्तु नियमों के अंतर्गत समान वस्तुएँ हैं।

18. प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और, इसलिए, विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में उत्पाद का था।

##### **घ. घरेलू उद्योग का आधार एवं दायरा**

19. यह याचिका आवेदक घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात याचिकाकर्ता अथवा आवेदक कहा गया है) द्वारा दायर की गई है।

##### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

20. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सभी ज्ञात उत्पादकों, जिसमें इस याचिका के समर्थनकर्ता अर्थात् मैसर्स अमोली आर्गेनिक्स एंड रेक्न फार्मा केम भी शामिल है, के वास्तविक उत्पादन आंकड़े साक्ष्य के रूप में प्रदान करते हुए कोई सूचना नहीं दी है।

यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन इस संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है और वह "घरेलू उद्योग" के रूप में निश्चित किए जाने के लिए "अहं" है।

### **घरेलू उद्योग के विचार**

21. यह याचिका मैसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अलावा भारत में इस संबद्ध वस्तु के चार अन्य उत्पादक भी हैं। अमोली आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और रेकन डायगनास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस याचिका का समर्थन किया है। जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का उत्पादन तथा समर्थनकर्ताओं का उत्पादन मिलाकर कुल भारतीय उत्पादन का 88 प्रतिशत उत्पादन बनता था। स्वयं याचिकाकर्ता का उत्पादन भी जांच की अवधि में कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात बनता था और इसलिए याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है। इसके अतिरिक्त, निर्णायक समीक्षा के मामले में आधार की जांच करना अपेक्षित नहीं होता है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

22. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन जांच की अवधि में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भारतीय उत्पादन का एक बड़ा अनुपात विस्तृत जांच के लिए बन सकता है या नहीं बन सकता है और यह कि इस याचिका के समर्थनकर्ताओं अर्थात् मैसर्स अमोली आर्गेनिक्स लिमिटेड और रेकन फार्माकिम सहित सभी जात उत्पादकों के वास्तविक उत्पादन आंकड़ों का साक्ष्य प्रदान करने की कोई सूचना नहीं दी गई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अकेले याचिकाकर्ता का उत्पादन ही कुल भारतीय उत्पादन का 53 प्रतिशत उत्पादन बनता है और ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता के आधार पर निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ समर्थनकर्ताओं के आंकड़ों की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनता है और नियमों के अंतर्गत उसका आधार भी बनता है।

### **ड. विविध मुद्दे**

#### **विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

23. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित है:

(क) 15 वर्षों तक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के पश्चात अभी भी याचिकाकर्ता का यह तर्क है कि उसके कार्यनिष्पादन में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः, यह स्पष्ट है कि आवेदक को अपनी ही किसी अक्षमता के कारण यह कथित क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का मौजूदा सकारात्मक निष्पादन, जो क्षति के सभी प्रमुख पैरामीटरों में सुधार से स्पष्ट है, अपने ही कार्यनीतिक निर्णयों का परिणाम है जैसे पूंजी निवेश और क्षमता में वृद्धि तथा यह चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

(ख) यह देश के व्यापक जनहित में नहीं है कि विटामिन सी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया जाए, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के कारण संबंधित लागत को अंतरः इसके अंतिम प्रयोक्ताओं द्वारा ही वहन किया जाएगा जिसमें वहनीय अनिवार्य औपधियों की जरूरतमंद भारी गरीब आबादी शामिल है।

(ग) विगत 15 वर्षों से घरेलू उद्योग के अंतर्गत मौजूदा ढांचागत मुद्दों का निराकरण न करने में घरेलू उद्योग की उदासीनता के लिए भारत में प्रयोक्ता उद्योग को क्यों दंडित किया जाए।

(घ) आवेदक ने यह तर्क दिया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों मात्रा कम होने के बावजूद कई विदेशी न्याय क्षेत्रों ने इस पर पाटनरोधी शुल्क का उद्धवहन करना जारी रखा। आवेदक द्वारा जिन मामला विधियों का उल्लेख किया गया है वे विदेशी न्याय निर्णय हैं और वे वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं। द्वितीयतः प्रतिवादीगण निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान यूएई और ईरान से सफेद सीमेंट के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे जिससे पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण करने के लिए आयातों की अल्प मात्रा का मुद्दा विचार का एक प्रमुख विषय था।

(ङ) मई, 2013 के नवीन डीपीसीओ आदेश के अनुसार ड्रग फार्मुलेशन विनिर्माता अधिकतम खुदरा कीमत के प्रति बाध्य होते हैं परंतु बल्क ड्रग विनिर्माता कंपनियों पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। बल्क ड्रग विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क में पांच अन्य वर्षों के लिए विस्तार करने से विटामिन सी वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन पर विपरीत दुराग्रह पड़ेगा क्योंकि इससे भारत में ड्रग फार्मुलेशन का विनिर्माण करना अर्थक्षम नहीं रहेगा।

(च) आवेदक ने दावा किया है कि विटामिन सी के चीन स्थित निर्यातिकों को कार्टेल बनाने और कीमतें नियत करने का योग्य कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है। एक कार्टेल बनाने के पीछे का उद्देश्य उच्चतर कीमतें निर्धारित करके बाजार का अनुच्छेद के अनुसार चीन के विनिर्माताओं की एकाधिकारिता के परिणामस्वरूप कीमतों में 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। अतः, यदि ऐसा मामला है तो, आवेदक का यह तर्क स्वतः ही खारिज हो जाता है कि चीन से कम कीमतों पर निरंतर आयात हुआ है। इसके अतिरिक्त, यह घटना तो यूएस में घटित हुई थी और आवेदक में इस आशय का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं

कराया है कि क्या भारत में भी समान प्रक्रिया का ही अनुपालन किया जाता है या नहीं। यदि ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है तब भी इसका उपचार तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष होगा न कि डीजीएडी के समक्ष।

(छ) चीन के निर्यातिकों का एकाधिकारवादी व्यवहार पाटनरोधी विधि के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी कंपनी की बाजार में एकाधिकारिता है तो वह उच्चतर कीमतें प्रभारित करके बाजार का दोहन करेगी, न कि न्यूनतर कीमतों से।

(ज) जांच की शुरूआत करने से लेकर अब तक की 40 दिनों की अधिदेशित अवधि के पश्चात भी हितवद्ध पक्षकारों को संशोधित जांचावधि तथा क्षति अवधि के संबंध में संपूर्ण एवं अद्यतनीकृत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(झ) वर्तमान अवधि जो जांच की अवधि का हिस्सा है के आंकड़ों को गोपनीय नहीं रखा जा सकता है इसलिए जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ पाटन एवं क्षति दोनों के विश्लेषण में त्रुटि है।

(ञ) प्राधिकारी जांच की अवधि के लिए आंकड़े दायरे करने का हितवद्ध पक्षकार से अनुरोध नहीं कर सकते हैं, जबकि डीए ने उन आंकड़ों को प्रदान ही नहीं किया है जिन्हें वर्तमान जांच में यथार्थ एवं उपयुक्त माना गया है।

(ट) याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने में संगत प्रावधानों का गलत अर्थ लगाया है कि प्राधिकारी को अनिवार्यतः ही एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करनी चाहिए। किसी निर्णायक समीक्षा की शुरूआत केवल तभी की जा सकती है जब कोई हितवद्ध पक्षकार "समीक्षा की जरूरत को साक्ष्यांकित करते हुए सकारात्मक सूचना" के साथ अनुरोध करता है अथवा यदि प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि एक समीक्षा की शुरूआत करने के लिए "अच्छे एवं पर्याप्त आधार मौजूद हैं।"

(ठ) जांच की अवधि समाप्त होने तथा जांच की शुरूआत होने के बीच लगभग 6 माह का अंतराल है। जांच की अवधि को जांच की शुरूआत की तारीख के यथा संभव निकट की तारीख को समाप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जांच की शुरूआत से पहले प्रस्तुत किया गया आवेदन केवल अक्टूबर, 2012 – सितम्बर, 2013 की अवधि के लिए था जबकि जांच की अवधि का विस्तार अक्टूबर 2012 से दिसम्बर, 2013 तक है। प्रभावक तौर पर, आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों तथा जांच की शुरूआत के बीच 9 माह का अंतराल था और फिर भी प्राधिकारी ने जांच शुरूआत की कार्रवाई कर दी। आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि अक्टूबर 2012 से दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के आंकड़े अगस्त, 2014 में, जांच की शुरूआत के पश्चात प्रस्तुत किए गए।

(ड) वर्तमान जांच की शुरूआत करना विधि विरुद्ध है क्योंकि आधे-अधूरे आंकड़े, जो जांच की अवधि को कवर करने में असफल रहते हैं, डब्ल्यूटीओ एडीए के अनुच्छेद 11.2 तथा भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(1क) के आशय के अंतर्गत" समीक्षा की जरूरत के लिए साक्ष्यांकित सकारात्मक सूचना" बनने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। किसी समीक्षा की शुरूआत करने के लिए समीक्षा की जरूरत के लिए किसी हितवद्ध पक्षकार द्वारा साक्ष्यांकित सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करना एक पूर्वपेक्षा है। जांच की शुरूआत के समय ऐसी सूचना का न होने पर प्राधिकारी को समीक्षा की शुरूआत करने की विधि के अंतर्गत अनुमति नहीं है।

(ढ) गैर-परिमाणित गुणवत्ता अंतरों के मदेनजर घरेलू उद्योग की तुलना में आयातित माल को अधिमानता है।

### घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग के विचार निम्नलिखित हैं :

(क) अधिनियम एवं नियमावली के ऐसी कोई समय-सीमा विहित नहीं हैं जिसके पश्चात पाटनरोधी शुल्क में विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। विधिक प्रावधान यह उल्लेख करते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है तो पाटनरोधी शुल्क में समय-समय पर विस्तार किया जा सकता है।

(ख) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना जनहित के विपरीत होगा, यह कहा जा सकता है कि विगत में अधिरोपित किए गए पाटनरोधी शुल्क के कारण उपभोक्ताओं पर कोई वास्तविक विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितवद्ध पक्षकार ने यह स्थापित करने के लिए कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का अंतरः आम जनता पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

(ग) पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन भारत में घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाले पाटन का निवारण करना है, न कि उपभोक्ताओं पर शास्ति लगाना।

(घ) याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई जांच की अवधि के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और उनके अगोपनीय पाठ की प्रति भी सार्वजनिक फाइल में रखने के लिए प्रस्तुत की गई थी।

(ङ) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के लिए याचिका हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करने और अन्य सूचना प्रदान करने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त नहीं है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

25. हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों के संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

(क) जहां तक विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस तर्क का संबंध है कि भारत में पाटनरोधी शुल्क से संबंधित ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें 15 वर्ष की अवधि के पश्चात भी पाटनरोधी शुल्क में विस्तार किया गया हो और इस शुल्क में विस्तार नहीं किया जा सकता है; प्राधिकारी यह धारित करते हैं कि अधिनियम एवं नियमावली में ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके पश्चात पाटनरोधी शुल्क में विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। धारा 9क(5) में स्पष्ट प्रावधान है कि अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले ही प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात वह निष्प्रभावी हो जाएगी, बशर्ते कि केंद्रीय सरकार किसी समीक्षा में यदि यह विचार हो कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार, समय-समय पर ऐसे अधिरोपण की अवधि में अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनः विस्तार कर सकती है। अतः, विधिक प्रावधान इस तथ्य का स्पष्टतः यह उल्लेख करते हैं कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति पाटन बने रहने तथा घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना बनी रहेगी तो पाटनरोधी शुल्क की समयावधि में समय-समय पर विस्तार किया जा सकेगा। घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप क्षति होने की पर्याप्त सूचना का उल्लेख है, जिसका प्राधिकारी द्वारा यह जांच प्रारंभ किए जाने से पहले परीक्षण किया गया और प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर ही प्राधिकारी ने इस जांच की शुयआत की है।

(घ) प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि एक निर्णायक समीक्षा जांच में पाटनरोधी शुल्क को तब तक अधिरोपित किया जाना अपेक्षित होता है जब तक जांच से यह प्रदर्शित होता है कि उक्त शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(ग) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना जनहित के विपरीत होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध करने के लिए कोई भी सूचना प्रदान नहीं कराई है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का जनहित पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि विगत में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं पर कोई वास्तविक विपरीत प्रभाव नहीं हुआ है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाले पाटन की अनुचित प्रक्रियाओं का समाधान करना है।

(घ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क से उपभोक्ताओं को लंबे समय तक दंडित करना है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य किसी भी शास्ति लगाना नहीं है। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य भारत में घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाले पाटन का निवारण करना है। यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह परिमाणित नहीं किया है कि पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ा है अथवा भारी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ङ) जहां तक आयातों की अल्प मात्रा होने तथा ऐसी परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के संबंध में घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह मुद्दा वर्तमान मामले में संगत (प्रासंगिक) नहीं है क्योंकि इस मामले में आयातों की मात्रा बहुत अधिक है।

(च) जहां तक डीपीसीओ की अनुप्रयोज्यता का सवाल है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य इस उत्पाद के उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करना होता है। यह भी नोट किया जाता है कि उपभोक्ताओं ने यह स्थापित नहीं किया है कि विटामिन सी पर अगले पांच वर्षों तक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करते रहने से यह किस तरह विटामिन सी ड्रग को वहन करने योग्य कीमतों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य के विपरीत होगा और कैसे इस ड्रग फार्मुलेशन को भारत में विनिर्मित करना लाभकर नहीं रहेगा। हर हाल में, मई 2013 के ड्रग कीमत नियंत्रण आदेश के अनुसार विटामिन सी (बल्क ड्रग) को डीपीसीओ आईर के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। मई, 2013 से पहले यह डीपीसीओ आईर के अंतर्गत कवर होता था।

(छ) जहां तक उत्पादन संघीकरण तथा भारत के बाहर न्यायालय में मामलों के संबंध में घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वह इस जांच के दायरे की परिधि से बाहर है।

प्राधिकारी ने उस कीमत पर विचार किया है जिस पर इस वस्तु का चीन से भारत को आयात किया गया है और वह कीमत जिस पर चीन से अन्य देशों को इस वस्तु का निर्यात किया गया है।

(ज) यह याचिका अक्टूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 तक की अवधि को जांच की अवधि मानते हुए दायर की गई थी, प्राधिकारी ने अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि को जांच की अवधि मानते हुए यह जांच यह अनुमति प्रदान करने के लिए प्रारंभ की थी जिससे कि प्राधिकारी को सर्वाधिक अभिनव अवधि अपनाने का अवसर मिल सके। याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी द्वारा अपनाने का अवसर मिल सके। याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई जांच की अवधि के लिए आंकड़े प्रदान कराए हैं और उसकी एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी रख दी गई है, जिस को जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा देखा जा सकता है।

(झ) जहां तक गोपनीयता के दावे का संबंध है, प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उसकी विधि के अंतर्गत गोपनीयता के उपबंधों पर विचार करते हुए अनुमति दी है। प्राधिकारी यह उपादित करते हैं कि इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे प्राधिकारी की विगत पद्धति के अनुरूप हैं।

(ज) प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिका में जांच की अवधि वह अवधि होना अपेक्षित नहीं है जिसके लिए प्राधिकारी को जांच आयोजित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के लिए याचिका होना, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के लिए प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करने तथा अन्य सूचना प्रस्तुत करने की एक पूर्व शर्त होना आवश्यक नहीं है। जांच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के लिए सूचना प्रदान करने को कहा था। प्राधिकारी के समक्ष दायर की गई समस्त सूचना सार्वजनिक फाइल में रखी गई है जिससे विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार अपने हितों की रक्षा कर सकें। प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के लिए याचिका न होने से हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जांच की अवधि के लिए अपने प्रत्युत्तर दायर करने से निवारित नहीं किया जा सकता है।

(ट) जहां तक निर्णायक समीक्षा जांच अनिवार्यतः प्रारंभ करने के संबंध में घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच की शुरूआत विधिवत दस्तावेजी साक्ष्यों युक्त याचिका के आधार पर प्रारंभ की गई है।

(ठ) जहां तक सूचना की गोपनीयता और लागत निर्धारण सूचना सामान्य मूल्य से संबंधित साक्ष्य, कच्चे माल के आयात आंकड़ों और निर्यात कीमत से संबंधित साक्ष्य का प्रकटन न करने से संबंधित प्रस्तुतिकरणों का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही पद्धति के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने कच्चे माल की कीमतों से संबंधित साक्ष्य तथा निर्यात कीमत से संबंधित साक्ष्य प्रत्युक्ति प्रस्तुतिकरणों में प्रदान कराए हैं जिन्हें सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया है और सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध करा दिया गया है।

(ड) जहां तक अस्वीकार्य गुणवत्ता तथा सामग्री की नामंजूरी से संबंधित प्रस्तुतिकरण का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद का उत्पादन तथा उसकी आपूर्ति उन सभी अनुप्रयोगों के लिए की है जहां आयातित उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। याचिकाकर्ता ने सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना यह दर्शाते हुए प्रदान कराई है कि उसने 150,600 किलोग्राम माल की आपूर्ति पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड/पीरामल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को की है जिसमें से 500 किलोग्राम माल नामंजूर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, अस्वीकृत माल के लिए कंपनी ने विक्री संदाय के रूप में विचार नहीं किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कथित गैर-परिमाणित गुणवत्ता अंतरों के महेनजर घरेलू उद्योग की तुनला में आयातित माल को अधिमानता देने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति की गई वस्तु इस विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु नहीं है। नियमों में प्राधिकारी से यह विचार करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है। यह भी प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि सेस्टैट ने वर्ष 2000 (119) ईएलटी 308 में रिपोर्ट किए गए डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में यह निर्णय दिया है कि घरेलू उत्पाद तथा आयातित माल के बीच गुणवत्ता में अंतर होने का आशय यह नहीं है कि घरेलू उत्पाद आयातित उत्पाद के समान उत्पाद नहीं है।

(इ) प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि प्राधिकारी के समक्ष रिकार्ड में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि विटामिन सी बनाने वाले घरेलू उद्योग के गुजरात में बडोदरा के निकट स्थित संयंत्र को किसी सरकारी निकाय द्वारा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में बंद करा दिया गया है।

(ण) प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि प्राधिकारी के समक्ष रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि यूएसए तथा ईयू ने इस संबद्ध वस्तु के आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

### च. पाटन का आकलन – क्रियापद्धति और पैरामीटर

#### पाटन का निर्धारण

26. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने निर्धारित प्रारूप एवं स्वरूप में निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करके जांच शुरूआत अधिसूचना का प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

#### अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

27. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का तारीका अनुचित है क्योंकि (क) भारत चीन के लिए एक उपयुक्त तुल्यरूप देश नहीं है, (ख) भारतीय उत्पादकों की तुलना में चीन के उत्पादकों के प्रचालन का पैमाना बहुत बड़ा है जिसके परिणामस्वरूप चीन में उत्पादन लागत कम रहती है और, (ग) भारत में विटामिन सी के उत्पादक 2 किटो एल गुलोनिक एसिड, जो संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित मुख्य कच्चा माल है का चीन से आयात करते हैं जबकि चीन के उत्पादक 2 किटो एल गुलोनिक एसिड विनिर्माण और उसका उपयोग ग्राही रूप से करते हैं और प्रापण आदि से जुड़ी संवर्धनात्मक कीमत की बचत करते हैं।

28. भारत को यूनाइटेड किंगडम से निर्यात कीमत के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य अनुनज्ञे है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एक उपयुक्त तुल्यरूप बाजार अर्थव्यवस्था वाला तृतीय देश नहीं है यूनाइटेड किंगडम में क्षतिपूर्ति लागत, विद्युत लागत तथा कच्चे माल की लागत चीन में इन सब की लागत की तुलना में बहुत अधिक है।

29. आवेदक को डाटा सेट में आईबीआईएस आंकड़ों से हटाकर अचानक डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में परिवर्तन कर देने की छूट नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों का चयन केवल इस आधार पर करना कि यह आंकड़े आवेदक के हितों के अधिक अनुकूल हैं, इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उचित प्रक्रिया मानकों का उल्लंघन होता है।

#### घरेलू उद्योग के विचार

30. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए, उन्होंने इस संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

(क) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा इस हालात में नहीं दिया जा सकता है जहां प्रमुख शेयरधारकों में से एक राज्य स्वामित्व वाला/नियंत्रित निकाय हो। यूरोपियन कमीशन ने संगत रूप से यह धारित किया है कि उन मामलों में देश के हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है जहां राज्य स्वामित्व वाले/नियंत्रित निकाय का भारी शेयर हो। यह विगत में किए गए हस्तक्षेपों का ही प्रश्न नहीं है बल्कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने के पश्चात भवित्य में किए जाने वाले राज्य के संभावित हस्तक्षेप की संभावना का भी प्रश्न है जो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किए जाने के लिए संगत है।

(ख) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है तब तक कि प्रत्युत्तरदाता चीन के निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर देते हैं कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विष्टियों की कीमत "पर्याप्ततः बाजार मूल्यों को प्रतिक्षिप्ति करती है।" घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि "पर्याप्ततः प्रतिक्षिप्ति बाजार मूल्यों" का व्यापक निर्वचन किया गया है जिसका आशय है कि इन अंतर्राष्ट्रीय विष्टियों की लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमतों से तुलनीय होना चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यह तथ्य सकलतः अपर्याप्त है कि चीन जन.गण. में प्रचलित कीमतों इन कीमतों के तुलनीय है।

(ग) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विष्टियों में उपयोगी वस्तुएं शामिल हैं : घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि संबंधित उत्पाद का उत्पादन करने के लिए एक प्रमुख उपयोगी मद के रूप में विद्युत एवं ईंधन की जरूरत होती है। सर्व सम्यततः, जबकि विद्युत आपूर्ति करने वाला निकाय राज्य के स्वामित्व वाला निकाय होता है तथापि ईंधन प्रदाय करने वाले से संबंधित अपर्याप्त सूचना ही उपलब्ध है। निर्यातक द्वारा यह सिद्ध नहीं किया गया है कि इन उपयोगी वस्तुओं की कीमतें बाजार मूल्यों का प्रतिक्षिप्ति करती हैं।

(घ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर देते हैं कि उनकी बहियों की लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानदंडों के अनुरूप की जाती है : घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन के निर्यातकों ने यूरोपियन कमीशन द्वारा उनको बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा नामंजूर कर दिए जाने के विरोध में बार-बार विरोध किया है और एक ऐसी स्थिति में जहां चीन के निर्यातक यह सिद्ध करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी बहियां चीन की जीएपी के समतुरूप हैं। इन मामलों में चीन की कंपनियां यह तर्क देती रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानदंडों का अनुपालन करने का आग्रह करना विधि संगत नहीं है। यूरोपियन कमीशन ने यह धारित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानदंडों का अनुपालन करने के आग्रह की जरूरत यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है कि वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित राजस्वों एवं व्ययों परिसंपत्तियों एवं देयताओं यथार्थता एवं उपयुक्तता सही है। यूरोपियन कमीशन का यह उद्धरण दिया जा सकता है कि इस पहलू के संबंध में लेखाओं की विश्वसनीयता तब तक स्थापित नहीं की जा सकती है जब तक कि बहियां अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानदंडों के अनुरूप न हों।

(इ) यदि एक पैरामीटर भी पूरा नहीं होता है तब भी बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है : घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि यूरोपियन कमीशन ने बार-बार यह आग्रह किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि चीन के प्रतिवादी निर्यातक नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रत्येक पैरामीटर के संबंध में जांच में सफल नहीं हो जाते हैं।

(च) उत्तरदायित्व/दायित्व : घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि यह प्राधिकारी का उत्तरदायित्व नहीं है कि वह यह सिद्ध करें कि प्रतिवादी कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था माहौल के अंतर्गत प्रचालन कर रही हैं और वे बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने की हकदार हैं। इसके विपरीत, चीन के प्रतिवादी निर्यातकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सिद्ध करें कि बाजार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

(छ) रूपांतरण : घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि ऐसी स्थिति में जहां मौजूदा शेयरधारकों ने अपनी उत्पादन सुविधाएँ स्वयं स्थापित नहीं की हैं बल्कि उन्हें किसी अन्य पक्षकार से अधिग्राप्त किया है, वहां बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है तब तक कि इस अंतरण की प्रक्रिया को दस्तावेजी साक्षों के जरिए पूर्णतया सिद्ध नहीं कर दिया जाता है।

(ज) समूह से समग्र रूप में प्रत्युत्तर : घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता है कि जब तक कि प्रतिवादी कंपनी तथा उसका समूह समग्र रूप से यह दावा नहीं करता है। यदि इस समूह का भाग बनने वाली एक या अधिक कंपनियां ने अपना प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है तो बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे को इस बात पर ध्यान दिए बिना ही अस्वीकार किया जा सकता है कि इस समूह की अन्य कंपनियां विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने और उसकी विक्री करने में अंतर्गत ही किया जाना चाहिए।

(झ) ऊपर उल्लिखित अनेक शर्तों का पूरा करने में असफल रहना ही चीन के प्रतिवादी निर्यातकों के लिए यह निर्णय करना पर्याप्त है कि चीन की प्रतिवादी कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए।

(ज) चीन के किसी भी निर्यातक ने वर्तमान मामले में न तो निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया है।

(ट) इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर इस कारण से नहीं किया जा सकता है कि संगत सूचना याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं है।

(ठ) भारत को अन्य देशों से निर्यात कीमत को भी इस कारण से ग्रहण नहीं किया जा सकता है कि अन्य देशों से आयात कीमत पर संबद्ध देश से आयातों के कारण प्रभाव पड़ सकता है।

(इ) याचिकाकर्ता ने भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का दावा किया है।

### चीन जन. गण. के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे की प्राधिकारी द्वारा जांच

31. पाटनरोधी नियमावली के अनुवंध-1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि:

"7. गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत अथवा विनिर्भीत मूल्य, अथवा ऐसे तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर किया जायेगा अथवा जहां संभव न हो वहां किसी अन्य तर्क संगत आधार पर, भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप में संदर्भ अथवा प्रदत्त कीमत सहित विधिवत समायोजित कीमत जिसमें तर्क संगत लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सके, के आधार पर किया जायेगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तर्क संगत ढंग से, संबंधित देश और प्रश्नाधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन किया जायेगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भरोसेमंद सूचना पर समुचित ध्यान दिया जायेगा। निश्चित समयसीमा के अंदर, जहां आवश्यक हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के बारे में किसी समान मामले में की गई जांच को भी ध्यान रखा जायेगा। जांचकर्ता पक्षकारों को बिना किसी अनुचित विलम्ब के बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपर्युक्त चयन के बारे में सूचना दी जायेगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए तर्क संगत समय प्रदान किया जायेगा।"

32. इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली के अनुवंध-1 के अंतर्गत निर्धारित संगत प्रावधान निम्नलिखित हैं :

8. (1) वाक्यांश "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश" का अभिप्रायः किसी ऐसे देश से होता है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि वह देश लागत अथवा कीमत निर्धारण ढांचे के अंतर्गत बाजार सिद्धांतों पर प्रचालन नहीं कर रहा है; जिससे कि उक्त देश में होने वाली किसी पण्य की विक्री, उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुरूप, पण्य के उचित मूल्य को प्रदर्शित नहीं करती है।

(2) यह प्रकल्पना होगी कि कोई ऐसा देश गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा जिसे वर्तमान जांच से पहले की तीन वर्षों की अवधि के दौरान डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में निर्धारित किया गया है अथवा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। बशर्ते कि, तथापि, गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश अथवा उस देश की संवर्धित फर्में इस प्रकल्पना का खंडन निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसी सूचना और साक्ष्य प्रदान करके इस प्रकल्पना का खंडन यह सिद्ध करके कर सकती हैं कि उक्त देश उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के आधार पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक मामले में निम्नलिखित प्रतिमानों पर विचार करेंगे कि क्या :

(क) उक्त देश में कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, आउटपुट बिक्रियों और निवेश सहित कीमतों, लागतों और अंतर्निविष्टियों के संबंध में सबविधित फर्मों का निर्णय मांग एवं आपूर्ति को प्रदर्शित करने वाले बाजार संकेतकों के प्रत्युत्तर में, इस संबंध में राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं और क्या प्रमुख अंतर्निविष्टियों की लागत पर्याप्त बाजार मूल्यों को प्रतिविम्बित करती है।

(ख) इन फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली द्वारा क्रियान्वित की गई भारी विकृतियों, खासकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते में डाले गए, विनिमय व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए भुगतान के संबंध में की गई विकृतियों के अध्यधीन है।

(ग) यह फर्में दिवालियापन और संपदा विधियों के अध्यधीन होती हैं जो इन फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी प्रदान करती है।

(घ) विनिमय दर संपरिवर्तन बाजार दरों पर किया जाता है।

शर्त यह है कि, तथापि, यह कि जहां यह प्रदर्शित होता है कि इस पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के आधार पर लिखित रूप में इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है कि ऐसी एक या अधिक फर्मों के लिए बाजार परिस्थितियां पाटनरोधी जांच के अध्यधीन मौजूद हैं, वहां निर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ-7 और इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय पैराग्राफ 01 से 06 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुप्रयोग कर सकता है।

(4) उप-पैराग्राफ (2) में किसी वस्तु के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी ऐसे देश को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं, जो संगत प्रतिमान के अव्याप्त विस्तृत मूल्यांकन, जिसमें उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिमान शामिल हैं, के आधार पर, इस मूल्यांकन को एक सार्वजनिक दस्तावेज के प्रकाशित करके, इस मूल्यांकन को एक सार्वजनिक दस्तावेज में प्रकाशित करके, किसी ऐसे देश द्वारा जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है, अथवा माने जाने के लिए निर्धारित किया गया है।"

33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में भारत द्वारा तथा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा की गई पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप निर्यातिक देश द्वारा या निर्यातिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग इस प्रकल्पना का खंड किए जाने के अध्यधीन माना गया है।

34. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/ निर्यातिक ने प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरूआत नोटिस के प्रत्युत्तर में न तो प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर किया है अथवा न ही उन्होंने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन करने की मांग ही की है।

35. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संगत नियमों के रूप में किया है।

#### चीन जन.गण. के उत्पादकों और निर्यातिकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

36. जहां तक अन्य हितवद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि भारत को यूनाइटेड किंगडम की निर्यात कीमत के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य अननुमेय है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम एक उपयुक्त तुल्यरूप बाजार अर्थव्यवस्था वाला तृतीय देश नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उन्होंने सामान्य मूल्य की संरचना यूनाइटेड किंगडम के आंकड़ों के आधार पर नहीं की है। जहां तक हितवद्ध पक्षकारों के इस

तर्क का संबंध है कि उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उपयुक्त नहीं है, प्राधिकारी ने रिकार्ड में उपलब्ध सभी सूचना पर विचार किया है। यह पाया गया कि तृतीय देशों से भारत को निर्यात कीमत प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध था। तथापि, इससे पाटन मार्जिन में भारी वृद्धि प्रदर्शित होनी चाहिए। वस्तुतः याचिकार्कर्ता ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि प्राधिकारी को सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए अन्य देशों से भारत को आयात कीमत पर विचार करना चाहिए। इसलिए प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि अपनाई गई क्रियापद्धति कम से कम निर्यातकों एवं उपभोक्ताओं के लिए अधिक अनुकूल है। यह भी नोट किया जाता है कि चीन के किसी भी उत्पादक ने इस संबंध में कोई परिमाणित दावा नहीं किया है। पुनः यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने गैर-वाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन भी नहीं किया है।

37. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि भारतीय उत्पादकों एवं चीन के उत्पादकों के बीच उत्पादन प्रक्रिया और तकनीकी अंतर को देखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तृतीय देश में संरचित कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए और यह कीमत चीन से ईश्य को निर्यात कीमत पर आधारित होनी चाहिए, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि अनुबंध-1 के पैरा-7 में कई वैकल्पिक क्रियापद्धतियों का प्रावधान किया गया है और उसमें ऐसे गैर-वाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से अन्य देशों को कीमत शामिल नहीं है। वास्तव में, यदि चीन में लागत या कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को पैरा-7 और 8 में विनिर्दिष्ट कारणों से नहीं अपनाया जा सकता है तो इसका आशय यह है कि चीन से यूरोप को की गई निर्यात कीमत को भी नहीं अपनाया जा सकता है।

38. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और चीन की प्रतिवादी कंपनियों द्वारा गैर-वाजार अर्थव्यवस्था का खंडन न किए जाने के अभाव में प्राधिकारी चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के साथ आगे बढ़ना अधिक उपयुक्त समझते हैं। चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी प्रस्तावित निर्धारण के प्रयोजनार्थ सामान्य तौर पर चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं।

39. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-1 के पैरा-7 को ध्यान में रखकर किया है। चीन जन.गण. से भारत में आयातित संबद्ध उत्पादों के लिए सामान्य मूल्य की संरचना घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई सूचना के अनुसार प्रमुख कच्चे माल की खपत, मुख्य कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, संपरिवर्तन लागत, व्याज, घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तर पर एसजीए पर विचार करते हुए की गई है। व्याज का अपवर्जन करते हुए विक्री लागत के 5 प्रतिशत की अनुमति तर्कसंगत लाभ के लिए दी गई है इस तरह निर्धारित सामान्य मूल्य अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

#### चीन जन.गण. के उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

40. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को प्रत्युत्तर नहीं दिया है, इसलिए चीन जन.गण. से आयातों के संबंध में निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर किया है। याचिकार्कर्ता ने निर्यात कीमत का दावा भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों, आईबीआईएस द्वारा यथारिपोर्टित आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से भी सौदावार आयात आंकड़ों का अधिप्रापण किया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारी संख्या में जांच में अपनाई गई परम्परा के अनुसार डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया है और भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर विचार करते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। अतः, आईबीआईएस आंकड़ों से डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर आकस्मिक परिवर्तन नहीं हैं। याचिकार्कर्ता घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत समायोजन चीन जन.गण. के निर्यातकों से असहयोग के मद्देनजर किया गया है। इस तरह निर्धारित निर्यात कीमत अधोलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

#### पाटन मार्जिन

41. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, पाटन मार्जिन का निम्नवत निर्धारण किया गया है। यह देखा जाता है कि यह पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक एवं महत्वपूर्ण है।

सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन रेंज
यूएस डालर/किग्रा	यूएस डालर/किग्रा	यूएस डालर/किग्रा	%	%
***	***	***	***	110-140

### छ. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का निर्धारण

42. क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों के विचार निम्नलिखित हैं :

(क) घरेलू विनिर्माता इस विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए अंतिम स्तर के मध्यवर्ती उत्पाद 2-कीटोगलुकोनिक एसिड का अभी भी चीन से आयात कर रहे हैं। कच्चे माल की कीमत तथा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू विनिर्माताओं को इस मध्यवर्ती उत्पाद के आयातों के कारण घाटा सहन करना पड़ा है। वर्ष 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और इसके परिणामस्वरूप आयात मंहगे हो गए। इस तर्क के समर्थन में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में रेकन के लिए रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है।

(ख) चीन के निर्यातक भारतीय घरेलू विनिर्माताओं की तुलना में अधिक लागत प्रतिस्पर्धी हैं। इस स्थिति को अमोली आर्गेनिक्स (2012) के प्रबंध निदेशक श्री मनीष दोषी के अभिकथन द्वारा समर्थित किया जा सकता है; “इंजीनियरिंग और रसायन के रूप में, दुभाग्यवश चीन का फार्मस्युटिकल उद्योग भारतीय फार्मस्युटिकल उद्योग की तुलना में बेहतर है ..... चीन का फार्मस्युटिकल उद्योग पूर्णतया लागत प्रभावी है क्योंकि वे पूर्णतया लागत प्रभावी हैं।”

(ग) आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़े यह सिद्ध नहीं करते हैं कि उसे वास्तविक क्षति हुई है और न ही वे यह सिद्ध करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने से वास्तविक क्षति की पुनरावृत्ति होगी।

(i) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में अवाध वृद्धि नहीं हुई है।

(ii) मांग में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर उसी अवधि के दौरान आयातों में 11 प्रतिशत की गिरावट आई।

(iii) संस्थापित क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। आवेदक के क्षमता उपयोग में कोई गिरावट नहीं आई है।

(iv) आवेदक की घरेलू विक्री मात्रा तथा मूल्य में भी वृद्धि हुई है।

(v) आवेदक के बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

(vi) घरेलू उद्योग की विक्री कीमत में गिरावट मई 2013 से पहले एनपीपीए द्वारा इस विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिकतम विक्री कीमत में कटौती के कारण आई है।

(vii) रेकन ने अपने समर्थन पत्र में यह उल्लेख किया है कि उसने सस्ते आयातों के कारण विटामिन सी का उत्पादन करना बंद कर दिया है। तथापि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रेकन के राजस्व एवं अर्जन में वर्ष 2008-09 की तुलना में वर्ष 2011-12 में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार रेकन के लिए जो निषेधात्मक पहलू थे वे हैं विनियामक कीमत निर्धारण में प्रतिकूल परिवर्तन, कच्चे माल, जिसका आयात किया गया, की कीमत में अस्थिरता और उच्च उत्पादन एकत्रीकरण जोखिम क्योंकि यह केवल विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में अंतर्गत है।

(viii) यदि रेकन, जो इस विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन ही करता है, अपनी राजस्व वृद्धि में बढ़ोत्तरी कर सकता है और इसका स्वस्थ प्रचालन एविडिटा है, तो आवेदक, जो कि उसी उद्योग माहौल में प्रचालन कर रहा है, को भी घाटा नहीं होना चाहिए था।

(ix) उपर्युक्त के मद्देनजर इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों और आवेदक द्वारा वास्तविक क्षति के किए गए दावों के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।

(घ) वर्तमान जांच में क्षति आंकड़े केवल बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए ही प्रदान कराए गए हैं। आवेदक को इस आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों के लिए तो क्षति से संबंधित आंकड़े प्रदान करने चाहिए थे। जिनके लिए यह दावा कर्ता है कि उन सभी का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का 88 प्रतिशत उत्पादन बनता है।

(ङ) क्षति जांच अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में गिरावट समग्र रूप में तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में आई है।

(च) आवेदक से संबंधित आर्थिक पैरामीटरों पर आधारित क्षति का अभाव है क्योंकि क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, विक्री बाजार हिस्सा, मालसूची, उत्पादकता, पारिश्रमिक, वेतन और रोजगार के रूप में आवेदक के कार्यनिष्पादन में भारी सुधार हुआ है।

(छ) इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांचों में घरेलू उत्पादकों में से चार ने लागत एवं क्षति से संबंधित आंकड़े प्रदान करने से मना कर दिया, इसलिए हम यह प्रस्तुत करते हैं कि प्राधिकारी यह आकलन करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों को डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.1 की अपेक्षाओं के अनुरूप कोई क्षति हो रही है।

(ज) पिछली समीक्षा में, संबद्ध वस्तु के केवल दो घरेलू उत्पादक थे। इस समय, संबद्ध वस्तु के पांच घरेलू उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग निश्चय ही सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है। नए उत्पादक निश्चय ही किसी ऐसे बाजार में प्रवेश नहीं करेंगे जहां क्षति हो रही हो या वह सुविचारित रूप से लाभप्रद न हो।

(झ) आवेदक के खर्चों में भारी वृद्धि के कारण कारित की गई क्षति की सीमा को आयातों द्वारा कारित क्षतिकारी प्रभावों से पृथक कर देना चाहिए।

(झ) संबद्ध देश के आयातों द्वारा कोई कीमत अवमंदन अथवा निग्रहण प्रभाव कारित नहीं किया गया है क्योंकि विक्री कीमत तथा उत्पादन लागत में गिरावट हुई है। विक्री लागत में यह कमी 2 किटों एल गुलोनिक एसिड की कीमत में कमी के परिणामस्वरूप हुई है। इसलिए, आयातों ने कीमतों में भारी मात्रा में अवमंदन नहीं किया है और न ही उसने कीमतों में वृद्धि होने से निवारित किया है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

(ट) विटामिन सी की अधिकतम विक्री कीमत को राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा विनियमित किया जाता है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई उर्ध्वगामी प्रवृत्ति एनपीपीए द्वारा अधिरोपित अधिकतम सीमा के अध्यधीन रही है।

(ठ) आवेदक की विक्री कीमत इसकी उत्पादन लागत से अधिक रही है और इसलिए आवेदक को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए और वह किसी भी कीमत निग्रहण का सामना नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादकों ने सर्वाधिक अभिनव अवधि में अपनी विक्री कीमतों में वृद्धि की है।

(ड) आवेदनपत्र स्वयं ही स्पष्टतः यह दर्शाता है कि आवेदक द्वारा उपगत किए गए क्षतिपय व्यय जैसे मूल्यहास, पारिश्रमिक और ब्याज किसी भी प्रकार की क्षति के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों की तुलना में अधिक उत्तरदायी थे। लाभ एवं निवेश पर प्रतिलाभ हास का संबंध आवेदक के उपर्युक्त व्ययों में वृद्धि से है। निवेश पर प्रतिलाभ और लाभ वर्ष 2012-13 में उस अवधि के दौरान ऋणात्मक हो गया जब आधार वर्ष की तुलना में मूल्यहास में 98 प्रतिशत वृद्धि, पारिश्रमिक और वेतन में 58 प्रतिशत वृद्धि तथा ब्याज में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त, उत्तरवर्ती वर्षों में विगत वर्ष की तुलना में मजदूरी एवं वेतन तथा ब्याज में पुनः 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। आवेदनक के मूल्यहास तथा पारिश्रमिक एवं वेतन में लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ एवं निवेश पर प्रतिलाभ पर प्रभाव पड़ना लाजमी था।

(ठ) घरेलू उद्योग द्वारा अन्यों के साथ-साथ आयातों की मात्रा, कीमत अधोरदन, घरेलू विक्री, लाभ और मांग में बाजार हिस्सा (ग्राही मांग को शामिल करते हुए एवं अपवर्जित करते हुए) के संबंध में उद्धृत किए गए आंकड़े उसके द्वारा अपनी याचिका में अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान कराए गए अद्यतन अनुलग्नकों में उद्धृत किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं।

(ण) आवेदक के नकद लाभ में कमी होने का कारण निवेश में वृद्धि होना है। खासकर, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को सकल लाभ हो रहा है परंतु उसके निवेश में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उसके नकद लाभ में कमी आई है।

### घरेलू उद्योग के विचार

43. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

(क) पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बाजबूद संबद्ध आयात भारी मात्रा में पाइट कीमतों पर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा चीन के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अंतर्लयन करने के कारण हुआ है। इसके अतिरिक्त, चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार चीन से इस उत्पाद के नियर्ता वास्तव में भारत में उत्पाद के भारी उच्चतर नियर्तों को प्रदर्शित करते हैं।

(ख) आयात भारी मात्रा में घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन कर रहे हैं।

(ग) आयातों की उत्तराई कीमत न केवल घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम है बल्कि वह घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और गैर-क्षतिकारी कीमत से भी कम है।

(घ) मौजूदा जांच की अवधि में पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक एवं बहुत अधिक हैं।

(ङ) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का अवमंदन हो रहा है। यूएस डालर में भारी मात्रा में मूल्य वृद्धि होने के बावजूद आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है जिसके कारण घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में कमी करने पर मजबूर होना पड़ा।

(च) उत्पादन और विक्री मात्रा में वृद्धि केवल इस कारण से हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने चीन के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए कम कीमत वाले उत्पाद मुकाबला करने का प्रयास किया।

(छ) घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह के रूप में भारी गिरावट आई है। लाभप्रदता एवं निवेश पर प्रतिलाभ वर्ष 2012-13 से ऋणात्मक हो गया है जबकि क्षति अवधि में नकद लाभ में भारी गिरावट आई है।

(ज) कीमत पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास विपरीत रहा है।

(झ) 2-किटोग्लुकोनिक एसिड से विटामिन सी का उत्पादन करने से इस उत्पाद का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल का कीमतों अथवा विनिमय दर की अस्थिरता से कच्चे माल और परिष्कृत उत्पाद दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ा होगा। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन परिवर्तनों से केवल उत्पाद की लाभप्रदता पर ही प्रभाव कैसे पड़ सकता है। वास्तव में 2-किटोग्लुकोनिक एसिड से विटामिन सी में सकारात्मक मूल्यवर्धन पर विचार करते हुए भारतीय मुद्रा में मूल्यहास होने से घरेलू उद्योग को अपनी लाभप्रदता में सुधार करने में सहायता मिलनी चाहिए।

(ज) भारतीय उद्योग तथा चीन के उद्योग के निष्पादन में अंतर के संदर्भ में वार्षिक रिपोर्ट में प्रबंध निदेशक का एक अभिकथन है। वार्षिक रिपोर्ट में किए गए अभिकथन घरेलू उद्योग के निष्पादन में दावाकृत गिरावट उत्तरदायी नहीं है।

### प्राधिकारी द्वारा जांच

44. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने प्रस्तुतिकरणों में दिए गए विभिन्न तर्कों पर विचार किया है और घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता की जांच प्राधिकारी के समक्ष किए गए इन तर्कों के आलोक में की है। उपलब्ध आंकड़ों एवं सूचना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से मौजूदा पाठन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है। इसलिए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाठन एवं क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच की कार्रवाई करने से पहले घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है।

45. हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों के संबंध में प्राधिकारी ने निम्नलिखित प्रेक्षण किए हैं :

(क) जहां तक 2-किटोग्लुकोनिक एसिड के आयातों, कच्चे माल की कीमतों और विनिमय दर की अस्थिरता के संबंध में दिए गए तर्कों के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद का संबंध 2-किटोग्लुकोनिक एसिड से विटामिन सी के उत्पादन से है। इसके अतिरिक्त, कच्चे माल की कीमतों अथवा विनिमय दर की अस्थिरता का कच्चे माल और परिष्कृत उत्पाद दोनों की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है। यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि यह परिवर्तन वरणात्मक रूप से किस तरह केवल इस उत्पाद की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में, 2-किटोग्लुकोनिक एसिड से विटामिन सी में सकारात्मक मूल्यवर्धन पर ध्यान देते हुए, भारतीय मुद्रा में मूल्यहास होने से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सुधार होने में सहायता मिलनी चाहिए।

(ख) जहां तक चीन के और भारतीय उत्पादकों की संगत प्रतिस्पर्धात्मकता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस तर्क के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि यह संगत प्रतिस्पर्धात्मकता क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट के लिए किस तरह उत्तरदायी हो सकती है। प्राधिकारी से क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार या पतन पर प्रकाश डालना अपेक्षित होता है। प्राधिकारी को क्षति के संबंध में निष्कर्ष निकालते समय घरेलू उद्योग की निर्यातिकों के साथ तुलना करना अपेक्षित होता है।

(ग) जहां तक अन्य घरेलू उत्पादकों से क्षति आकलन का संबंध है, प्राधिकारी यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक के प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के रूप में इन उत्पादकों का उपचार करने के लिए कोई सूचना प्रदान नहीं की है। तथापि, चूंकि अकेले बजाज के हेल्पर्स के बजाज के इस संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात है और इस प्रकार वह घरेलू उद्योग कहलाने का अधिकारी है, इसलिए अन्य उत्पादकों के लागत निर्धारण/क्षति आंकड़ों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने इस प्रक्रिया का अनुपालन विगत के कई मामलों में भी किया है।

(घ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि जांच की अवधि में इस उत्पाद के आयातों में गिरावट आई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस उत्पाद के आयात निर्बाध रूप से और उत्पादन एवं खपत के संगत रूप में बहुत अधिक रहा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का यह तर्क कि चीन के सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार चीन से इस उत्पाद के निर्यात वास्तव में इस उत्पाद के भारत को भारी मात्रा में निर्यात दर्शाते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि याचिका

में गौण स्रोत के आधार पर विचार की गई आयात मात्रा डीजीसीआईएंडपीस में रिपोर्ट की गई आयात की मात्रा की तुलना में आयातों की कम मात्रा दर्शती है।

(ङ) जहां तक इस तर्क का संबंध में समर्थनकारी घरेलू उत्पादकों से प्राप्त आंकड़ों के अभाव में हितबद्ध पक्षकारों को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने से निवारित किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए देखा जाना अपेक्षित है।

(च) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि इस उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की संख्या में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसका अभिप्रायः यह नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति बढ़ने की संभावना नहीं है।

(छ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा उपगत व्यय में भारी वृद्धि हुई है, प्राधिकारी ने आंकड़ों की जांच और उसका सत्यापन, वर्तमान निर्धारण के लिए उन्हें अपनाए जाने से पहले, किया है।

(ज) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति मूल्यहास, पारिश्रमिक तथा ब्याज में वृद्धि के कारण हुई है, प्राधिकारी ने आंकड़ों का सत्यापन किया है और यह पाया है कि लाभप्रदता में गिरावट इन पैरामीटरों में वृद्धि के कारण नहीं हुई है।

46. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्गत होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव, और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए ....." कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरुद्धन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि को कम करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

47. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए पूर्वोक्त नियमावली के अनुसार उन सभी अभिसूचकों पर विचार किया गया जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा स्टाक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्रापण, पाटन की मात्रा एवं पाटन मार्जिन आदि।

48. वर्तमान जांच प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णयक समीक्षा जांच है। नियम 23 में यह प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में भी नियम 11 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसलिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के प्रावधानों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित, विचार किया है। प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या क्षति कारित करने वाले पाटन का मुकाबला करने के लिए मौजूदा साधन पर्याप्त नहीं हैं।

49. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसका प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तब तक वह ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते कि, केंद्रीय सरकार का किसी समीक्षा में यह विचार है कि इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, तो यह समय-समय पर, इस अधिरोपण को पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह बढ़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी।

50. मौजूदा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति, यदि कोई, के बीच कारणात्मक संबंध तथा क्षति की मौजूदगी की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव तथा उसका कीमत एवं लाभप्रदता पर प्रभाव की जांच की है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति की जांच, नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनने वाले मैसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड से संबंधित सूचना पर विचार किया है।

51. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर विचार किया है और उसका उपयुक्ततापूर्वक समाधान किया है। प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार क्षति पैरामीटरों का विश्लेषण किया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने, जहां कहीं अधिपत्रित हुआ, गोपनीयता प्रदान कर दी और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा उसका प्रकटन हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया। गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को, जहां कहीं संभव हुआ, यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दर्ज की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रदान करें। तदनुसार, पाटित आयातों के मात्रा एवं कीमत प्रभाव की जांच निम्नवत की गई है:

### पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

52. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच प्राधिकारी द्वारा निम्नवत की गई है :

#### मांग और बाजार हिस्सा

53. प्राधिकारी ने संबद्ध देश तथा अन्य देशों से आयातों की कुल मात्रा तथा मूल्य का आकलन करने के लिए डीजीसीआईएंडएस से अधिप्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। मांग एवं बाजार हिस्से से संबंधित स्थिति निम्नलिखित है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
मांग (ग्राही को छोड़कर)	एमटी	2706	2903	3121	2807
मांग (ग्राही को शामिल करते हुए)	एमटी	2745	2945	3158	2893
घरेलू उद्योग की विक्री (ग्राही को छोड़कर)	एमटी	807	919	1087	1077
घरेलू उद्योग की विक्री (ग्राही को शामिल करते हुए)	एमटी	846	962	1123	1163
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	एमटी	1,143	1,173	1,256	1,056
आयात - चीन	एमटी	653	680	674	556
आयात - अन्य देश	एमटी	103	131	105	118
मांग में बाजार हिस्सा (ग्राही को छोड़कर)					
घरेलू उद्योग	%	29.83%	31.66%	34.81%	38.36%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	42.23%	40.40%	40.23%	37.62%
आयात - चीन	%	24.13%	23.43%	21.60%	19.81%
अन्य देश	%	3.81%	4.51%	3.36%	4.21%
मांग में बाजार हिस्सा (ग्राही को शामिल करते हुए)					
घरेलू उद्योग	%	30.82%	32.65%	35.56%	40.19%
अन्य भारतीय उत्पादक	%	41.64%	39.81%	39.77%	36.50%
आयात - चीन	%	23.79%	23.09%	21.34%	19.22%
अन्य देश	%	3.75%	4.45%	3.33%	4.09%

54. यह देखा जाता है कि इस उत्पाद की मांग में वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में मांग में जांच की अवधि में मामूली सी वृद्धि प्रदर्शित होती है। घरेलू उद्योग की विक्री मात्रा में अति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयातों में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई है और फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध देश से आयात भारी मात्रा में बने रहे।

#### आयात मात्रा तथा संबद्ध देश की हिस्सेदारी

55. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में निर्बाध रूप से अथवा भारत में उत्पादन और खपत के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में निर्बाध रूप से अथवा भारत में उत्पादन एवं खपत के संगत रूप से भारी वृद्धि हुई है।"

56. डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान कराए गए सौदावार आंकड़ों पर विचार करते हुए क्षति अवधि के लिए आयात की मात्रा निम्नवत है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
चीन जन.गण.	एमटी	653	680	674	556
अन्य देश	एमटी	103	131	105	118
कुल आयात	एमटी	756	811	779	674
निम्नलिखित के संबंध में पाठित आयात :					
• कुल आयात	%	86.37 %	83.82%	86.53%	82.44%
• उत्पादन	%	32%	32%	28%	25%

57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद चीन जन.गण. से आयात निर्बाध रूप से तथा देश में उत्पादन एवं खपत की तुलना में बहुत अधिक बने रहे।

58. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायिक समीक्षा जांच है, इसलिए आयातों की वर्तमान मात्रा को घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आलोक में देखने की जरूरत है।

59. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है तथा चीन के बाजार हिस्से में कमी आई है, प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों के संबंध में प्रपाती हास हुआ है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायिक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी को न केवल सतत क्षति का विश्लेषण करना अपेक्षित होता है बल्कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में संभावित क्षति की जांच करना भी अपेक्षित होता है।

### घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों का कीमत प्रभाव

60. पाठित आयातों का कीमत पर प्रभाव के संबंध में नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है :

"नियम 18 के उप-नियम (2) में यथा-उल्लिखित कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाठित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन हुआ है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्य कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना होगा अथवा कीमतों को बढ़ने से निवारित करना होगा जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती।"

61. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन के संबंध में की है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल विक्री प्राप्तण (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की उत्तराई लागत से की है।

### कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण प्रभाव

62. पाठित आयातों का कीमत पर प्रभाव के संबंध में यह जांच की गई कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाठित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों का प्रभाव कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना है अथवा कीमतों को बढ़ने से रोकना है जिनमें अन्यथा भारी मात्रा में वृद्धि हुई होती।

63. कीमत अधोरदन का निर्धारण संपूर्ण जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाठित आयातों के उत्तराई मूल्य की तुलना उसी अवधि के लिए घरेलू उद्योग के निवल विक्री प्राप्तण से करके किया गया है। इस उद्देश्य के लिए आयातों के उत्तराई मूल्य का परिकलन 1 प्रतिशत प्रहस्तन प्रभार तथा संबद्ध देश से आयात कीमत के डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में रिपोर्ट किए गए मूल्य पर लागू आधारभूत सीमाशुल्क जोड़कर किया गया है। घरेलू उद्योग के निवल विक्री प्राप्तण का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई रिवेट, डिस्काउंट और कमीशन तथा संदर्भ केंद्रीय उत्पाद शुल्क को घटाया गया है।

64. कीमत अधोविक्रयण का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से आयातों की उत्तराई कीमत की तुलना जांच की अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत के साथ की गई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
उत्तराई कीमत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	83	70	66
निवल विक्री प्रापण	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	84	76	76
कीमत अधोरदन	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
कीमत अधोरदन	%	***	***	***	***
कीमत अधोरदन रेज	%				30-60%
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/किग्रा				***
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/किग्रा				***
कीमत अधोविक्रयण	%				110.70%
कीमत अधोविक्रयण रेज	%				100-120%

65. इस संबंध में प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं :

(क) संबद्ध देशों से आयातों का उत्तराई मूल्य घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से वास्तविक रूप से कम है जिससे भारी सकारात्मक कीमत अधोरदन प्रदर्शित होता है।

(ख) आयातों की उत्तराई कीमत तथा गैर-क्षतिकारी कीमत के बीच भी तुलना की गई। यह नोट किया गया कि संबद्ध देश से आयातों की उत्तराई कीमत जांच की अवधि में गैर-क्षतिकारी कीमत से बहुत कम है।

66. इस प्रकार प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से आयातों को उत्तराई मूल्य ने भारी कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण कारित किया है।

#### पाठित आयातों का कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव

67. पाठित आयातों के कीमत निग्रहण प्रभाव की जांच की उत्पादन लागत, निवल विक्री प्रापण और संबद्ध देश के उत्तराई मूल्य के संदर्भ में की गई।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
आयातों की उत्तराई कीमत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	83	70	66
विक्री लागत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	99	98
विक्री कीमत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	84	76	76

68. यह नोट किया जाता है कि आयातों की उत्तराई कीमत जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की विक्री लागत और विक्री कीमत से पर्याप्ततः कम है। यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान विक्री लागत कमोबेश रूप से स्थिर बनी रहीं परंतु उत्तराई कीमत से समता बनाए रखने के लिए निवल विक्री प्रापण में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार, आयात बाजार में कीमतों का निग्रहण कर रहे हैं।

69. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में और घरेलू उद्योग द्वारा आयात कीमतों पर अपनी विक्री करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होगा। निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ भी भारी क्रृष्णात्मक हो जाएगा।

70. जहां तक इस दलील का संबंध है कि घरेलू उद्योग पर कोई निगहण अथवा अवमंदन प्रभाव नहीं हुआ है; प्राधिकारी यह उपपादित करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान विक्री कीमत में गिरावट आई है, जिसे अमहत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यह नोट किया जाता है कि जहां विक्री लागत कमोवेश रूप से समान स्तर पर बनी रहीं वहीं विक्री कीमत और आयात कीमत में गिरावट आई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस अवधि में विक्री कीमत में भारी गिरावट आई, जो आयात कीमत में गिरावट के कारण घटित हुई।

### घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक पैरामीटरों की जांच

71. पाटनरोधी नियमावली के अनुवंध-॥ में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति का निर्धारण करने में इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्गत होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाइट आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित जांच शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल है विक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक गिरावट; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले उपादान, पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, मालमूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूँजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित क्रृष्णात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच यह व्यक्त करती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविकी क्षति हुई है, तथापि, वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन यथावश्यक परिवर्तनों सहित आधार पर करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या मौजूदा साधन उस पाटन का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त है जो क्षति कारित कर रहा है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति पैरामीटरों की जांच निम्नवत की गई है।

### घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग, विक्री

72. सत्यापित आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री मात्रा की जांच निम्नवत की गई है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
क्षमता	एमटी	960	1,200	1,320	1,320
उत्पादन	एमटी	865	955	1,140	1,177
क्षमता उपयोग	%	90%	80%	86%	89%
घरेलू उद्योग की विक्री (ग्राही में)	एमटी	846	962	1123	1163
घरेलू उद्योग की विक्री (ग्राही का अपवर्जन करते हुए)	एमटी	807	919	1087	1077

73. उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि -

- (क) घरेलू उद्योग ने मांग एवं विक्री में बढ़ोत्तरी होने की प्रत्याशा में अपनी क्षमता में वृद्धि की है।
- (ख) क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्री मात्रा में भी वृद्धि हुई है।
- (ग) घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

(घ) घरेलू उद्योग को विक्री मात्रा के रूप में क्षति नहीं हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों के संबंध में प्रपाती गिरावट आई है जैसा कि अधोलिखित तालिका से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए प्राधिकारी को न केवल सतत क्षति की जांच करना अपेक्षित है बल्कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में क्षति की संभावना की जांच करना भी अपेक्षित है।

### लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

74. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ एवं नकदी प्रवाह की जांच निम्नवत की गई है:

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
विक्री लागत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	99	98
विक्री कीमत	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	84	76	76
लाभ/हानि	रुपए/किग्रा	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	10	-31	-26
लाभ/हानि	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	11	-42	-34
कर-पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	26	-12	-2
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	34	5	6
निवेश पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	16	-8	-2

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान कर एवं ब्याज पूर्व लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिलाभ के रूप में भारी गिरावट आई है।

### मालसूची

76. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर की जांच की है जो निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
स्टॉक (मात्रा) औसत	एमटी	***	***	***	***

77. उपर्युक्त सूचना से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची में जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

### रोजगार एवं वेतन

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा संदर्भ वेतन में भी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
रोजगार	संघर्ष	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	108	110
वेतन	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	123	158	171

### उत्पादकता

79. घरेलू उद्योग की उत्पादकता की माप श्रमिक उत्पादकता और प्रतिदिन उत्पाकता आउटपुट के रूप में किया गया है और प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्पादकता में उत्पादन के अनुरूप ही वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	105	123	124
उत्पादकता प्रतिदिन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	110	132	136

### घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. संबद्ध देश तथा अन्य देशों से आयात कीमतों, लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा वे अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का उत्तराई मूल्य घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से काफी कम है जिससे भारतीय बाजार में भारी कीमत अधोरदन हो रहा है। इस उत्पाद का कोई अर्थक्षम प्रतिस्थानी नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु की मांग ने भारी वृद्धि प्रदर्शित की है और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं हो सकता है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए उत्तराधारी प्रमुख कारक आयातों की उत्तराई कीमत और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है।

### पाटन मार्जिन की मात्रा

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।

### वृद्धि

82. घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों की जांच करने पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर घरेलू उद्योग उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्री के संबंध में भारी विपर्यय वृद्धि सहन करनी पड़ी है; लाभप्रदता में गिरावट आई है जैसा कि लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों से देखा जा सकता है। उस कीमत पर विचार करते हुए जिस पर निर्यातिक भारतीय बाजार में माल का पाटन कर रहे हैं; पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण करने से पाटित आयातों की मात्रा में उद्रेक होगा जिससे विकास से और अधिक कमी आएगी।

वृद्धि प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
उत्पादन	%	-	9%	16%	3%
विक्री मात्रा	%	-	12%	15%	-1%
विक्री कीमत	%	-	-20%	-11%	0%
लाभ लाख रुपए	%	-	-89%	-476%	5%
निवेश पर प्रतिलाभ	%	-	-83%	-151%	-25%
क्षमता उपयोग	%	-	-12%	8%	3%

### **पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता**

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के दौरान घाटा हुआ है। याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि ऐसी स्थिति में कोई नया निवेश करना अर्थक्षम नहीं होगा।

### **क्षति का समग्र आकलन**

84. अतः, जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि पाटित आयातों की मात्रा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा निर्वाध रूप से दोनों ही रूपों में बहुत अधिक रही है। पाटित आयातों का कीमतों पर प्रभाव के संबंध में यह कहा जा सकता है कि पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में, भारी कीमत अधोरुद्धन किया गया है और इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन हुआ है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में लाभ, नकद लाभ तथा निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों के संबंध में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है।

### **कारणात्मक संबंध**

85. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी से, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा उन अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना भी अपेक्षित होता है जो उस समय पर घरेलू उद्योग को क्षति कारित कर रहे हों, जिससे इन अन्य ज्ञात कारकों से कारित क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जा सके। इस संबंध में जो कारक संगत हैं उनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उन आयातों की मात्रा एवं मूल्य जिनकी विक्री पाटित कीमतों पर नहीं की गई हो, मांग में संकुचन अथवा खपत के मापदंडों में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं तथा घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रविधि में विकास और निर्यात निष्पादन, तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। यह जांच की गई कि क्या नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध इन अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग की क्षति में अपना योगदान दिया है।

### **क. अन्य देशों से आयात तथा अन्य ज्ञात कारक**

86. इस विचाराधीन उत्पाद के अन्य देशों से आयातों की मात्रा या तो न्यूनतम है अथवा उनका आयात उच्चतर कीमतों पर किया गया है। इसलिए, अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं कर रहे हैं।

### **ख. मांग में संकुचन**

87. आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में वर्ष 2012-13 तक वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई। तथापि, जांच की अवधि में इसकी मांग में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में गिरावट को उस एक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसने घरेलू उद्योग के निष्पादन में प्रभावित किया हो।

### **ग. खपत के मापदंड में परिवर्तन**

88. खपत के मापदंड में कोई भारी परिवर्तन प्राधिकारी के संज्ञान में नहीं आया है और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण किया है।

### **घ. घरेलू एवं विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं**

89. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। घरेलू बाजार में किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया की जानकारी प्राधिकारी को नहीं दी गई है। घरेलू उत्पादक एक दूसरे के साथ और साथ ही संबद्ध वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत पर संबद्ध वस्तु की उत्तराई मूल्य का प्रभाव पड़ता है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की उत्तराई कीमत घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से कम है। रिकार्ड में ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो दर्शाता हो कि घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ गई हो/उसमें इतना अधिक परिवर्तन आ गया हो कि घरेलू उद्योग को यह क्षति परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।

### **ड. प्रौद्योगिकी में विकास**

90. जांच से प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई विकास प्रदर्शित नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति कारित हो सकती है।

### **च. घरेलू द्वारा निर्यात**

91. याचिकाकर्ता इस विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करता है। तथापि, उसके निर्यात उसकी कुल विक्री का बहुत छोटा सा अंश बनता है। इसके अतिरिक्त, क्षति का आकलन करने के लिए घरेलू विक्रियों से संबंधित आंकड़ों पर ही यथासंभव सीमा तक विचार किया गया है।

### **छ. उत्पादकता**

92. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। अतः, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है।

93. इसलिए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचीबद्ध तथा ज्ञात पैरामीटरों ने घरेलू उद्योग को क्षति कारित नहीं की है।

#### ज. पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना

##### घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

94. घरेलू उद्योग ने पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं।

(क) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बहुत अधिक है और पाटन मार्जिन भी बहुत उच्च है।

(ख) आयात में शुरूआत से ही बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मूल जांच की अवधि तथा उत्तरवर्ती जांच की अवधियों के बीच आयातों की मात्रा भारी वृद्धि हुई है।

(ग) यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो चीन से आयातों से घरेलू कीमतों का भारी अधोरदन हुआ है।

(घ) यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होने की संभावना निम्नलिखित कारणों से है :

(i) पिछली निर्णायिक समीक्षा जांच में पाटन मार्जिन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद भी निरंतर बना रहा।

(ii) चीन के निर्यातिक संघ ने निर्यात के आशय से विटामिन सी की कीमतों निर्धारित करके विश्व बाजार में विटामिन सी के लिए लगभग एकाधिकारिता स्थापित कर ली है।

(iii) चीन के विटामिन सी के निर्यात ने कम कीमतों के कारण विश्व बाजार को अपने कब्जे में कर लिया है।

(iv) संबद्ध देश में निर्यातकों की क्षमता भारतीय मांग और गृह बाजार में उसकी घरेलू मांग की तुलना में बहुत अधिक है।

(v) संबद्ध देश के उत्पादक अपने कुल उत्पादन का लगभग 60-100 प्रतिशत का निर्यात कर रहे हैं।

(vi) भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। ऐसा मामला होने पर संबद्ध देश से बाजार में इतनी कम कीमत वाली संबद्ध वस्तु की उपलब्धता निश्चय ही घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव डाल रही है।

(vii) संबद्ध देश से तृतीय देशों को निर्यात की मात्रा पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में भारतीय बाजारों में इनके निर्यातों में वृद्धि हो जाएगी।

(ङ) आयातों का उत्तराई मूल्य वह कीमत है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। इसलिए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में संबद्ध देश के उत्पादक आक्रामक ढंग से भारतीय बाजार को अपना निशाना बनाएंगे।

(च) घरेलू उद्योग को कीमत पैरामीटरों के रूप में क्षति हो रही है। इसके अतिरिक्त, यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समय में विस्तार नहीं किया जाता है और पाटन जारी रहा तो संबद्धित क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

#### विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

95. इस संबंध में विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) चीन के उत्पादकों की भारी बेशी उत्पादन क्षमताओं के संबंध में आवेदक द्वारा प्रदान कराए गए साध्य यह विशेषीकृत नहीं करते हैं कि क्या प्रदाय की यह क्षमता निर्यातों के लिए है या उनकी घरेलू खपत के लिए। इसमें स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या आपूर्ति की यह क्षमता भारत के लिए है। किसी सकारात्मक साध्य के अभाव में आवेदक के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(ii) इस समय आवेदक को कोई क्षति नहीं हो रही है और इसके अतिरिक्त, वह यह सिद्ध करने के लिए "सकारात्मक साध्य" देने में असफल हो गया कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

(iii) आवेदक यह सिद्ध करने के लिए कोई भी भरोसेमंद साध्य देने में असफल रहा है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से क्षतिकारी पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी। आवेदक ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि चीन के

निर्यातकों की निर्यातोन्मुखता, भारतीय बाजार में कीमत आकर्षकता और इस तथ्य के आधार पर कि चीन के उत्पादकों के मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता है यह कहा जा सकता है कि क्षतिकारी पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि चीन से निर्यातों के लिए भारत ही प्रमुख बाजार नहीं है। विशेषकर, चीन से इस संबद्ध वस्तु के कुल निर्यातों का केवल 0.7 प्रतिशत निर्यात ही भारत को होता है।

### **प्राधिकारी द्वारा जांच**

96. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो भविष्य में पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है; निर्यातक की विक्री मात्रा की प्रवृत्ति तथा अपने गृह बाजार में एवं तीसरी दुनियां की निर्यात बाजारों में इसकी कीमतों की प्रवृत्ति की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों पर भी विचार किया गया है।

97. वर्तमान जांच चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णयिक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का सतत अधिरोपण अधिपत्रित है। उन्हें यह जांच करना भी अपेक्षित होता है कि क्या अधिरोपित शुल्क क्षतिकारी पाटन का उपशमन करने के आशयित प्रयोजन को पूरा कर रहा है। वर्तमान जांच में सतत पाटित आयात हुए हैं। शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इस उत्पाद का सतत पाटन होने की संभावना है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विगतवर्ती जांच एवं वर्तमान जांच दोनों में पाटन मार्जिन वहूत अधिक है और यह कि जहां तक संबद्ध वस्तु की मांग एवं कीमत का संबंध है, भारतीय बाजार में अनुकूल बाजार परिस्थितियां विद्यमान हैं, इसलिए प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण विद्यमान हैं कि शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में पाटन में तीव्रता आ सकती है। यह एक वस्तु स्थिति है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद भी भारतीय बाजार में संबद्ध देश संबद्ध वस्तु का अभी भी पाटन कर रहा है।

98. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. से पाटित आयातों की मात्रा इस तथ्य के बावजूद बहुत अधिक बनी हुई है कि संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है। संबद्ध देश से आयातों की मौजूदा मात्रा स्वयं ही यह दर्शाने के लिए बहुत अधिक है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने की पूर्ण संभावना है।

99. जहां तक वेशी क्षमताओं और भारत को संभावित निर्यात से संबंधित तर्क का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन के आपूर्तिकर्ताओं के पास भारी वेशी क्षमताओं की विद्यमानता के संगत विचार मौजूद हैं। इन वेशी क्षमताओं पर इस उत्पाद की घरेलू खपत तथा तीसरी दुनियां की बाजारों में चीन के उत्पादकों द्वारा प्रतिबद्ध मात्रा को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना अपेक्षित है। चीन के किसी भी उत्पादक ने यह दावा नहीं किया है कि तीसरी दुनियां के देशों को किया गया कोई भी निर्यात दीर्घावधिक संविदा के अंतर्गत किया गया है और इस सीमा तक क्षमताएं चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध नहीं हैं।

100. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि चीन से भारत को इस वस्तु के निर्यात चीन से संपूर्ण विश्व के देशों को किए जा रहे कुल निर्यातों का केवल 0.7 प्रतिशत ही है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उससे कम से कम यह संभावना तो सिद्ध हो ही जाती है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो आयातों में और अधिक वृद्धि हो जाएगी।

101. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क काफी लंबी अवधि से अधिरोपित है और फिर भी घरेलू उद्योग ने क्षति का दावा किया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान निर्धारण वास्तविक सत्यापित सूचना पर आधारित है जो स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है।

102. प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति के पहलुओं की समानांतर जांच की है और यह उपपादित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भी घरेलू उद्योग को पाटन एवं उसके परिणामस्वरूप क्षति की संभावना बनी रहेगी। निम्नलिखित विश्लेषण पुनः यह दर्शाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति तीव्र होने/उसकी निरंतरता बने रहने की पूरी संभावना है।

#### **(i) मौजूदा एवं पिछले पाटन मार्जिन का स्तर**

103. पाटन मार्जिन का स्तर मूल जांच, पिछली निर्णयिक समीक्षा जांच तथा वर्तमान जांच सभी में बहुत अधिक है। यद्यपि घरेलू उद्योग के पास मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है, फिर भी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पाटित कीमतों पर होना अब भी जारी रहे। कीमत अधोरदन एवं कीमत अधोविक्रयण के स्तर पर विचार करते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पाटित आयातों की मात्रा में और अधिक वृद्धि होगी।

#### **(ii) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता**

104. वह कीमत जिस पर चीन जन.गण. से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, पाटन की निरंतरता और उसके तीव्रीकरण की संभावना की बहुत बड़ी संकेतक हैं। भारत में मौजूदा उत्तराई कीमत पर, सकारात्मक कीमत अधोरदन है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से चीन के उत्पादकों के लिए भारतीय कीमतें इतनी अधिक आकर्षक हो जाएंगी कि वे भारत को पाटित कीमतों

पर अपना निर्यात और अधिक तीव्र कर देंगे और इस बात की भारी संभावना है कि भारत के उपभोक्ता संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का भारी पैमाने पर आश्रय लेने लगेंगे।

### (iii) संबद्ध देश के उत्पादकों की निर्यातोन्मुखता

105. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन के उत्पादक/निर्यातक अत्यधिक निर्यात उन्मुखी हैं। भारत में इस संबद्ध वस्तु की भारी मांग तथा अनुकूल बाजार परिस्थितियों एवं इन उत्पादकों की उच्च उत्पादन क्षमता तथा निर्यातोन्मुखता पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में यह निर्यातक भारत को पाटित कीमतों पर अपने निर्यातों में वृद्धि कर देंगे।

### (iv) संबद्ध देश में भारी उत्पादन क्षमता

106. चीन में मौजूदा क्षमताओं के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि इस संबद्ध वस्तु की भारत में कुल मांग की तुलना में चीन में भारी उत्पादन क्षमता मौजूद है। चीन के किसी भी उत्पादक ने इस जांच में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में और निर्यात उन्मुखता पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि चीन के उत्पादक इन्हें क्षमता युक्त हैं कि वे इस संबद्ध वस्तु के विनिर्माण में लगे भारतीय विनिर्माण सेक्टर को पूरी तरह से अतिच्छादित करने की क्षमता रखते हैं।

### (v) तृतीय देशों में पाटन

107. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि पाटित कीमतों पर तीसरी दुनियां के देशों को भारी मात्रा में किए गए निर्यात विद्यमान हैं। संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर देने से संबद्ध वस्तु के आयातों में पाटित कीमतों पर आयात होने की संभावना और भी अधिक बढ़ जाएगी।

### (vi) इस साधन की गैर-मौजूदगी में कीमत अधोरदन, निग्रहण, अवमंदन

108. वह कीमत जिस पर चीन जन.गण, से भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जा रहा है उन कीमतों की स्पष्ट संकेतक हैं जिन पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में चीन से भारत को निर्यात किए जाने की संभावना है। जैसा कि अधोलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत में उत्तराई कीमत पर पाटनरोधी शुल्क के बिना भारी कीमत अधोरदन है। अतः, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से इन निर्यातकों के लिए भारतीय कीमतें और भी अधिक आकर्षक हो जाएंगी और इस बात की पूरी संभावना है कि भारी मांग होने के कारण भारतीय उपभोक्तागण उसका भारी मात्रा में आयात करेंगे। निर्यातक भी अपना उत्पाद भारतीय बाजार में सरणीयन करने के प्रति उत्साहित होंगे क्योंकि उनके पास अतिशय क्षमताएं हैं और वे अपने उत्पादों की विक्री अत्यधिक कम कीमत पर कर रहे हैं।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
निवल बिक्री प्राप्तण	रुपए/किग्रा	***
उत्पादन लागत	रुपए/किग्रा	***
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/किग्रा	***
आयातों का उत्तराई मूल्य	रुपए/किग्रा	***
कीमत अधोरदन	रुपए/किग्रा	***
कीमत अधोविक्रयण	रुपए/किग्रा	***
आयात कीमत पर लाभ/हानि	रुपए/किग्रा	***
ब्याज प्रति इकाई	रुपए/किग्रा	***
प्रति यूनिट मूल्यहास	रुपए/किग्रा	***
ब्याज एवं कर-पूर्व लाभ	रुपए/किग्रा	***
प्रति इकाई नियोजित पूँजी	रुपए/किग्रा	***
नकद लाभ	रुपए/किग्रा	***

109. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग के निष्पादन में कीमत पैरामीटरों के संबंध में वास्तविक गिरावट आएगी। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में यदि घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की विक्री आयात कीमतों पर करता है तो घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा, निवेश पर क्रृष्णात्मक प्रतिलाभ और नकद घाटा सहन करना होगा।

#### (vii) भूल अवधि तथा उत्तरवर्ती अवधियों में आयात मात्रा में भारी वृद्धि

110. पिछले मामलों तथा मौजूदा अवधि में रिपोर्ट की गई आयातों की मात्रा के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी होने के बावजूद चीन जन.गण. से आयातों की मात्रा बहुत अधिक रही है। जब पाटनरोधी शुल्क लगे होने की स्थिति में भी आयातों की मात्रा बहुत अधिक रही है तो पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में इस मात्रा में और अधिक वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। यह विश्वास करने की कोई दलील नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाठित आयातों की मात्रा में कमी आएगी।

#### (viii) संबद्ध देश द्वारा भारतीय बाजार में व्यापक बाजार हिस्सा

111. पाटनरोधी शुल्क अस्तित्व में होने के बावजूद चीन जन.गण. से आयातों का बाजार हिस्सा बहुत अधिक रहा है। पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की इस मात्रा में बढ़ोतरी होना अवश्यम्भावी है।

#### पाटन एवं क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

112. संबद्ध देश से आयातों की मौजूदा कीमत, घरेलू उत्पाद एवं आयातित उत्पाद के बीच कीमत अंतर, उत्पाद की कीमत संवेदनशीलता, प्रतिवादी निर्यातिकों तथा चीन के अन्य उत्पादकों की क्षमता, तीसरी दुनियां के देशों की बाजारों में पाटन, पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में तीव्रीकृत पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पूर्ण संभावना है।

#### क्षति मार्जिन एवं क्षति की मात्रा

113. प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध वस्तु की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग के लागत आंकड़ों पर विचार करते हुए किया गया है। चूंकि यह उत्पाद इस जांच की अवधि के कुछ भाग के लिए ड्रग कीमत नियंत्रण आदेश के अंतर्गत था इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई डीपीसीओ कीमत की तुलना क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देश से आयातों के उत्तराई मूल्य से की गई है, जो निम्नवत है :

#### क्षति मार्जिन तालिका

क्षति मार्जिन	मापन की इकाई	(गैर-क्षतिकारी कीमत के अनुरूप क्षति मार्जिन) राशि	डीपीसीओ के अनुरूप क्षति मार्जिन) राशि
सीआईएफ कीमत	रुपए/किग्रा	***	***
उत्तराई मूल्य	रुपए/किग्रा	***	***
डीपीसीओ कीमत	रुपए/किग्रा	-	***
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/किग्रा	***	-
क्षति मार्जिन	रुपए/किग्रा	***	***
क्षति मार्जिन	यूएस डालर/किग्रा	***	***
क्षति मार्जिन %	%	***	***
क्षति मार्जिन	% रेज	105-115	90-100

114. यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि यह अधिकतम है।

## प्रकटन पश्चात विवरण टिप्पणियां

### (क) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियां

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण आवृत्तीय प्रकृति के हैं और उनका इस प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

(क) विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क पिछले 17 वर्षों से अधिरोपित हैं और घरेलू उत्पादक इसमें पांच वर्षों का और विस्तार कराने की मांग कर रहे हैं।

(ख) याचिकाकर्ताओं द्वारा अत्यधिक गोपनीयता का आश्रय लिया गया है।

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद के विलेपित ग्रेड में गुणवत्ता संबंधी कई गंभीर कमियां हैं। इस विचाराधीन उत्पाद के उक्त ग्रेड का इस जांच के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए।

(घ) चीन के विनिर्माताओं और भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी में अंतर है। इसलिए, सामान्य मूल्य की संरक्षना करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति त्रुटिपूर्ण है। इसमें ग्राही रूप से विनिर्माण करने के बजाय 2केजीए का आयात करने के परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादकों द्वारा उपगत की गई उच्चतर इनपुट अधिप्रापण लागत में सामान्य मूल्य का समायोजन किया गया है।

(ङ) आवेदक से संबंधित आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर क्षति का अभाव है क्योंकि क्षमता, क्षमता उपयोग, विक्री, बाजार हिस्सा, मालसूची, उत्पादकता, पारिश्रमिक, वेतन और रोजगार के रूप में आवेदनकर्ता के निष्पादन में भारी सुधार हुआ है।

(च) स्पष्टतः न तो कोई कीमत निश्चय हुआ है अथवा न ही कोई कीमत अवमंदन और वह भी संबद्ध वस्तु के आयातों पर उपरोपित किया जा सकता है। विटामिन सी की उत्पादन लागत में 2केजीए का 50 प्रतिशत भाग होता है। इन्हीं कारणों में से एक के कारण चीन से आयातों का उत्तराई मूल्य समसामयिक अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहा है।

(छ) याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया चीन के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया से भिन्न है और यह लागत प्रभावी नहीं है, जिससे स्व-प्रेरित क्षति हुई है।

(ज) प्राधिकारी को प्रीमिक्स विनिर्माताओं के व्यापक हितों को संतुलित करते हुए उन पर विचार करना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था के बड़े भाग के हितों की रक्षा की जा सके। इस संबद्ध वस्तु पर फार्मास्युटिकल प्रयोजन के लिए पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा। वर्ष 2010 में, विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने और कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव होने से विनिर्माताओं को विटामिन सी के टेबलेट्स का उत्पादन बंद करने को बाध्य होना पड़ा था।

(झ) पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने से विटामिन सी का उत्पादन करना अर्थक्षम नहीं रह जाएगा – विटामिन सी के फार्मुलेशनों को राष्ट्रीय अनिवार्य औषधि सूची में शामिल किया गया है।

(ञ) नए डीपीसीओ आर्डर 2013 के अनुसरण में बल्क ड्रग विनिर्माताओं के लिए अधिकतम खुदरा कीमत को हटा देने के परिणामस्वरूप इस विचाराधीन उत्पाद की कीमत में आवेदक द्वारा 10 प्रतिशत से 45 प्रतिशत की रेंज में वृद्धि कर दी गई।

(ट) फार्मास्युटिकल प्रयोग के लिए आयात की गई विटामिन सी में गैर-फार्मास्युटिकल प्रयोग के लिए आयात की गई विटामिन सी से आसानी से अंतर किया जा सकता है, क्योंकि फार्मास्युटिकल प्रयोग के लिए विटामिन सी के निर्यातकों को भारत के भेज महानियंत्रक (डीजीसीआई) के पास पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, फार्मास्युटिकल उद्देश्यों के लिए विटामिन सी के आयातकों को भी आयात अनुज्ञापत्र अवाप्त करने की जरूरत होती है। इसलिए, इस तरह की छूट, सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर अपेक्षित होने के अलावा, इसका क्रियान्वयन भी अर्थश्रम है।

(ठ) आवेदक को क्षति से संबंधित आंकड़े कम से कम इस आवेदनपत्र का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों के संबंध में तो अवश्य दिया जाना चाहिए था, जो एक साथ लेने पर कुल घरेलू उत्पादन का 88 प्रतिशत बनने का दावा करता है।

(ड) संबद्ध देश से आयात की मात्रा में क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि में निर्बाध रूप से और उत्पादन एवं खपत के संबंध में गिरावट आई है।

(द) विटामिन सी की अधिकतम विक्री कीमत का विनियम राष्ट्रीय औपर्युक्ति कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा किया गया है और घरेलू उद्योग की कीमतों में बढ़ने की किसी भी प्रवृत्ति पर एनपीपीए द्वारा सीमा अधिरोपित की जा सकती है।

(ण) आवेदक की लाभप्रदता में गिरावट प्रदर्शित होती है, तथापि इस गिरावट के लिए स्पष्टतः आवेदक द्वारा उपगत किए गए कतिपय भारी खर्चों जैसे अवक्षयण, पारिश्रमिक और ब्याज को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है न कि संबद्ध वस्तु के आयातों को।

(त) आवेदक के नकद लाभ में गिरावट होने का कारण उसके निवेश में वृद्धि होना है। खासकर, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को सकल लाभ हुआ है परंतु निवेश में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप उसके नकद लाभ में गिरावट आई है।

(थ) आवेदक यह सिद्ध करने के लिए, कि शुल्क को समाप्त कर देने से क्षतिकारी पाटन की पुनरावृत्ति होगी, कोई भरोसेमंद साक्ष्य प्रदान करने में असफल रहा है।

(द) भारत चीन से निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार नहीं है। चीन के उत्पादकों की निर्यात उन्मुखता का ईयू और यूएस की ओर झुकाव है, न कि भारत की ओर। इसके अतिरिक्त, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चीन की विश्व में विटामिन सी के उत्पादन में लगभग एकाधिकारिता है जो पाटनरोधी शुल्क के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है।

(ध) विशेषकर, चीन से इस संबद्ध वस्तु के हो रहे कुल निर्यातों में से भारत को केवल 0.7 प्रतिशत का ही निर्यात किया जाता है। चीन के विनिर्माताओं के पास उत्पादन की अधिक सुविधाओं को स्पष्टतः अपेक्षित तथा क्षति के आसन्न चुनौती के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

(न) भारत में विटामिन सी के परिष्कृत फार्मुलेशनों की कीमत का विनियमन एनपीपीए द्वारा किए जाने पर भारत को इस संबद्ध वस्तु के निर्यातों के लिए बाजार को अधिक आकर्षक बना देती है।

(प) मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है।

(फ) चीन के विनिर्माता इस विचाराधीन उत्पाद के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी हैं, यह एक ऐसा तथ्य है कि इसे भारतीय घरेलू विनिर्माताओं द्वारा इसे स्वयं भी स्वीकार किया है।

(ब) यदि चीन के निर्यातकों ने इस विचाराधीन उत्पाद का पाटन करके विटामिन सी के लिए भारतीय बाजार में अपनी पकड़ बनाने चाहते तो चीन के निर्यातकरण कच्चे माल 2केजीए की कीमतों पर भारी वृद्धि कर सकते थे जिसके कारण भारत में विटामिन सी के बल्कि ड्रग विनिर्माताओं को भारी क्षति पहुंचती। यह नोट किया जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में चूंकि भारत में 2केजीए का कोई भी घरेलू विनिर्माता नहीं है इसलिए पाटनरोधीर जांच की शुरूआत करने का विकल्प भी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए थी।

(भ) आईबीआईएस आंकड़ों के बजाय डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों का प्रयोग किया गया जबकि आईबीआईएस आंकड़ों की विश्वसनीयता पर शंका करने का कोई कारण नहीं है।

(म) घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आंकड़ों की यथातथ्यता जो 2केजीए की आयात कीमतों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय करने की कीमतों में 25 प्रतिशत की प्रपाती गिरावट के बावजूद लगभग समान ही बनी रही।

(य) समान उत्पाद पर एनपीपीए कीमत नियंत्रण का प्रभाव जिसका घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी अवमंदनकारी प्रभाव हुआ।

(कक) आवेदक सकल लाभ आर्जित कर रहा है जो इसके आंकड़ों से अच्छी तरह से अभिदर्शित है और इसके अतिरिक्त, वह किसी कीमत नियंत्रण का सामना नहीं कर रहा है। निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ में हुई किसी भी गिरावट के लिए अभिकथित पाटित आयातों के अलावा बढ़े हुए असाधारण खर्चों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(खख) भारत में उत्पादन लागत के आधार पर संरचित सामान्य मूल्य अननुमेय है। इस संबद्ध वस्तु का उत्पादन किए जाने वाले मुख्य कच्चे माल 2 किटो एल गुलोनिक एसिड (2केजीए) की अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतों को प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की संगणना करने के लिए आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूंकि 2केजीए इस संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत का लगभग 50 प्रतिशत भाग होता है, इसलिए 2केजीए की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रयोग करने से सामान्य मूल्य उर्ध्वमुखी हो जाएगा।

(गग) प्राधिकारी को चीन के लिए सामान्य मूल्य की संरचना करते समय 2केजीए के आयातन से संबंधित उपर्युक्त इनपुट अधिप्रापण लागत एवं अटैंडेंट लागत का समायोजन करना चाहिए।

(घघ) पिछले पाटन मार्जिन का स्तर विधिक रूप से अवैध है।

#### **(घ) घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियाँ**

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए अधिकांश विवरण प्रस्तुतिकरण आवृत्तिक प्रकृति के हैं और उनका इस प्रकटन विवरण में पहले ही समाधान कर दिया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(क) वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद विटामिन सी है। विचाराधीन उत्पाद का दायरा इस जांच में भी वही रहेगा जो पिछली पाटनरोधी जांच में था।

(ख) रिकार्ड में उपलब्ध सूचना स्पष्टतः यह सिद्ध करती है कि याचिकाकर्ता के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात है।

(ग) प्राधिकारी ने चीन के सभी निर्यातकों को गैर-वाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के अंतर्गत प्रचालन करने वाला सही ही माना है क्योंकि चीन जन.गण. के किसी भी निर्यातक ने न तो कोई प्रत्युत्तर दिया और न ही वाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रश्नावली का प्रस्तुतिकरण किया।

(घ) सामान्य मूल्य का निर्धारण संरचित उत्पादन लागत पर विचार करते हुए किया है।

(ङ) इस जांच से यह सिद्ध हो गया है कि भारी पाटन की मौजूदगी है।

(च) पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद संबद्ध देश से इस उत्पाद के निर्बाध रूप से भारी आयात हुए।

(छ) वर्तमान क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में उत्पादन, क्षमता उपयोग के रूप में सुधार हुआ है। तथापि, कीमत प्रचालनों जैसे लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ, नकदी प्रवाह आदि के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी कमी आई है और वर्ष 2012-13 तथा जांच की अवधि में घाटा होने की सूचना दी गई है।

(ज) तथापि, पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर भारी अवमंदन प्रभाव पड़ेगा।

(झ) जांच की मौजूदा अवधि में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों ही सकारात्मक एवं पर्याप्त हैं।

(ज) प्रचलित पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोरदन सकारात्मक एवं बहुत अधिक है।

(ट) पाटनरोधी शुल्क के बिना आयात कीमत घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से वास्तव में कम है। इसलिए, यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो उपभोक्ताओं का झुकाव आयातित उत्पादों की ओर हो जाएगा जिससे इस उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि होगी।

(ठ) यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

(ड) गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण ऐसी वास्तविक लागत पर विचार करते हुए किया जाना चाहिए जहां नियत व्ययों को उत्पादन के आधार पर संविभाजित किया गया है।

(ढ) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

(ण) पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखना अपेक्षित है।

(त) शुल्क की सिफारिश निर्धारित राशि आधार पर यूएस डालर के रूप में की जानी चाहिए।

#### **(ग) प्राधिकारी द्वारा जांच**

117. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग तथा विरोधकर्ता हितवद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पश्चात किए गए अधिकांश प्रस्तुतिकरण आवृत्तिक प्रकृति के हैं और उनका इस प्रकटन विवरण में तथा इस अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना में उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत समाधान कर दिया गया है। किर भी, प्राधिकारी ने इन मुद्दों का आवश्यक समझी गई सीमा तक निम्नवत समाधान किया है :

(क) जहां तब इस तर्क का संबंध है कि इस आवेदन का समर्थन करने वाले सभी घरेलू उत्पादकों को क्षति से संबंधित सभी आंकड़े प्रदान कराए जाने चाहि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अकेले याचिकाकर्ता का उत्पादन ही कुल भारतीय उत्पादन का 53 प्रतिशत उत्पादन बनता है और ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता के आधार पर निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ समर्थनकर्ताओं के आंकड़ों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उड़ाए गए इस तर्क के संबंध में कि विटामिन सी पर पाटनरोधी शुल्क पिछले 17 वर्षों से लागू है और अब इसमें विस्तार नहीं किया जाना चाहिए; प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि नियमों में ऐसी किसी भी समय-सीमा का निर्धारण नहीं है जिसके आगे पाटनरोधी शुल्क का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। विधिक प्रावधान स्पष्टत: यह उल्लेख करते हैं कि यदि यह पाया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना बनी रहेगी तो पाटनरोधी शुल्क में समय-समय पर विस्तार किया जा सकता है। जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि पाटन और परिणामी क्षति तथा उसकी संभावना के पर्याप्त साक्ष्य है।

(ग) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध करने के लिए कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का जनता पर अंततः भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि विगत में अधिरोपित किए गए पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं पर कोई यथार्थ विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी भी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को क्षति कारित करने वाली पाटन की अनुचित प्रक्रियाओं का समाधान करना है।

(घ) जहां तक कम मात्रा में आयात होने तथा ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के संबंध में घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह मुद्दा इस मामले से प्रासंगिक नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में आयातों की मात्रा बहुत अधिक है।

(इ) जहां तक डीपीसीओ की अनुप्रयोज्यता का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य इस उत्पाद के उत्पादकों को समान अवसर प्रदान करना है। यह भी नोट किया जाता है कि उपभोक्ताओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि विटामिन सी पाटनरोधी शुल्क की अगले पांच वर्षों तक निरंतरता से किस तरह विटामिन सी ड्रग वहनीय कीमतों पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन के विपरीत होगा और भारत में इस ड्रग फार्मलेशन का विनिर्माण करना किस तरह से अव्यवहार्य हो जाएगा। किसी भी हाल में, मई, 2013 के भेषज कीमत नियंत्रण आदेश के अनुसार विटामिन सी (बल्क ड्रग) को डीपीसीओ आदेश के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। जबकि मई, 2013 से पहले इसे शामिल किया जाता था।

(च) यह याचिका अक्टूबर, 2012 से सितम्बर, 2013 तक की अवधि को जांच की अवधि के रूप में मानते हुए दायर की गई है। प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2013 तक की अवधि को जांच की अवधि मानते हुए की है जिससे कि प्राधिकारी अत्यधिक अभिनव अवधि को अपना सके। याचिकार्ता ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई जांच की अवधि के लिए आंकड़े प्रदान किए हैं और उसकी एक प्रति सार्वजनिक फाइल में रख दी गई है, जिसे इस जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी देखा गया।

(छ) जहां तक गोपनीयता के दावे का संबंध है प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और विधि के अंतर्गत गोपनीयता के प्रावधानों घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों तथा प्राधिकारी की पिछली परम्पराओं पर विचार करते हुए उसकी अनुमति दी गई है। प्राधिकारी यह प्रतिपादित करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में किए गए दावे प्राधिकारी की पिछली प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

(ज) जहां तक स्वीकार न किए जाने के योग्य गुणवत्ता एवं माल की अस्वीकृति से संबंधित प्रस्तुतिकरण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस उत्पाद का उत्पादन और उसका प्रदाय उन सभी अनुप्रयोगों के लिए किया है जहां आयातित उत्पाद का प्रयोग किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अभिक्षित अपरिमाणिक गुणवत्ता अंतर के मद्देनजर घरेलू उत्पाद की तुलना में आयातित उत्पाद को अधिमानता देने से यह सिद्ध नहीं होता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं आपूरित वस्तु इस विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद नहीं हैं।

(झ) जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि चीन के उत्पादकों तथा भारत में घरेलू उत्पादकों द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया और प्रविधि में अंतर है और इसलिए सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए अपनाई गई क्रियापद्धति वृटिपूर्ण है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य की संरचना प्राधिकारी द्वारा विगत में की गई भारी संख्या में ऐसी जांचों में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप की है।

(झ) कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह नोट किया जाता है कि भारत में समान उत्पाद की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है और इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन हुआ है। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में जांच से यह प्रदर्शित हुआ है कि लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ जैसे पैरामीटरों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में भारी गिरावट आई है। इस प्रकार इस जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है।

(ट) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क में विस्तार करने से विटामिन सी फार्मुलेशनों को बनाना महंगा पड़ा जाएगा, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जांच बल्क ड्रग के आयातों के संबंध में की गई है न कि फार्मुलेशनों के संबंध में। चूंकि विटामिन सी का पाटन किया जा रहा है और उससे क्षति हो रही है, इसलिए इस जांच का दायरा विटामिन सी के आयातों में उचित व्यापार प्रक्रियाओं के प्रयोग तक सीमित है।

(ठ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए आयात किए जा रहे विटामिन सी और गैर-फार्मास्युटिकल प्रयोग के लिए आयात किए जा रहे विटामिन सी के बीच आसानी से अंतर किया जा सकता है, प्राधिकारी एक बार पुनः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जांच इसके सभी प्रस्तुपों में बल्क ड्रग के आयातों से संबंधित है और प्राधिकारी का अधिदेश विटामिन सी के आयातों के संबंध में उचित व्यापार प्रक्रियाओं को लागू करना है।

(ड) जहां तक इस मुद्रे का संबंध है कि आईबीआईएस आंकड़ों की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों से प्रत्युत्तर न मिलने की स्थिति में सदैव सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को अपनाया है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी द्वारा डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों को विगत में ऐसी कई जांचों में अपनाया है जिनके लिए आईबीआईएस आंकड़े भी उपलब्ध थे।

(ढ) प्राधिकारी पुनः यह नोट करते हैं कि विटामिन सी (बल्क ड्रग) को मई, 2013 से पहले डीपीसीओ आदेश के अंतर्गत कवर किया जाता था। इसलिए, क्षति मार्जिन, गैर-क्षतिकारी कीमत तथा डीपीसीओ के अनुरूप क्षति मार्जिन के संबंध में औसत क्षति मार्जिन होना चाहिए।

(ण) जहां तक आयातित परिष्कृत उत्पाद तथा आयातित कच्चे माल के कीमत व्यवहार का संबंध है, यह सही है कि क्षति अवधि के दौरान इन दोनों की कीमतों में गिरावट आई है, परंतु परिष्कृत उत्पाद के मामले में यह गिरावट अधिक हुई जिससे घरेलू उद्योग की क्षति में बढ़ोतरी हुई।

### **(क्ष) भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्रे**

118. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण भारत में इस उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पाटन की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ को दूर करेगा, घरेलू उद्योग में गिरावट को कम करेगा और उपभोक्ताओं को इस संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में सहायता करेगा। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिवर्धित नहीं होगा और इसलिए, अंतिम प्रयोक्ता को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। अंतिम प्रयोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोत बनाए रख सकेंगे।

119. सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को कारित क्षति का उपशमन करना है जिससे भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपातरहित प्रतिस्पर्धा की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सके जो देश के आम हित में हो। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

### **ब. निष्कर्ष**

120. हिंदूदेश पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदान कराई गई सूचना और किए गए प्रस्तुतिकरणों और इस अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी के समक्ष रिकार्ड किए गए उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप क्षति की निरंतरता एवं पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति की संभावना की स्थिति के विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(क) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन हुआ है और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक एवं अर्थवान है। पाटित आयात क्षति अवधि में घरेलू उद्योग को क्षतिकारित कर रहे हैं।

(ख) यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन तीव्र होगा जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षति में वृद्धि होगी।

### **ट. सिफारिश**

121. उपर्युक्त निष्कर्ष निकालने के पश्चात प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करना अपेक्षित है।

122. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के न्यूनतर के बराबर निर्णयिक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने की सिफारिश करते हैं जिससे कि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा

सके। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से नियांति संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट राशि के अनुरूप पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

### शुल्क तालिका

क्र.सं .	शीर्षक/ उपशीर्षक	वस्तु विवरण	फार्मस ग्रेड (नीचे दिए गए* नोट के अनुसार)	उद्भव का देश	नियांति का देश	उत्पादक	नियांति	शुल्क राशि	यूनिट	मुद्रा
1.	29362700	विटामिन- सी	सभी फार्मस/ग्रेड	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	3.74	किग्रा	यूएस डालर
2.	29362700	विटामिन- सी	सभी फार्मस/ग्रेड	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. के अलावा कोई अन्य	कोई	कोई	3.74	किग्रा	यूएस डालर
3.	29362700	टामिन- सी	सभी फार्मस/ग्रेड	चीन जन.गण. के अलावा कोई अन्य	चीन जन.गण.	कोई	कोई	3.74	किग्रा	यूएस डालर

\*नोट : यह पाटनरोधी शुल्क विटामिन सी के सभी समरूपों पर लागू है। तथापि, विटामिन सी के सर्वाधिक सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले समरूप हैं – एस्कर्बिंग एसिड, जल- जाइलोएस्कर्बिंग एसिड, 3-आक्सो – एल – गुलोफर्नॉलैक्टोन (इनोल फार्म), एल -3-किटोश्रिओहेस्युरोनिक एसिड, लैक्टोन आदि, जैसा कि मैरेक इंडेक्स की प्रविष्टि संख्या "867" में वर्णित है।

### ड. आगे की प्रक्रिया

123. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थी आयातों का उत्तराई मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा यथानिर्धारित कर निर्धार्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8व, 9 एवं 9क को छोड़कर अन्य सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

124. केंद्रीय सरकार के इस जांच परिणाम से सुजित आदेशों के विरुद्ध सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क उत्पाद कर एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2015

### (FINAL FINDINGS)

**Subject:** Sunset review of anti-dumping duty imposed on the imports of Vitamin C originating in or exported from China PR.

**No. 15/10/2014 - DGAD:** Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

### A. BACKGROUND OF THE CASE

2. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the AD Rules or Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce,

Government of India, appointed under the Rules supra, had in the original investigation, recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of “Vitamin-C” (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR and Japan vide Notification No. 10/1/97/ADD dated 25th May, 1998 and definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 53/98-Cus dated 24th July, 1998.

3. WHEREAS, the Authority conducted a sunset review investigation in respect of the final anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods vide Notification No. 53/98-Cus dated 24th July, 1998 and examined whether cessation of anti-dumping duty was likely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry and recommended extension of anti-dumping duty imposed on the imports of the subject goods from China PR vide Notification No. 14/14/2002-DGAD dated 31st July, 2003. The duty was extended by the Central Government vide Customs Notification 159/2003-Customs dated 24th October, 2003.

4. WHEREAS, the Authority conducted second sunset review investigation and recommended extension of anti dumping duty vide Notification No. 15/16/2008 dated 21st May, 2009. The anti-dumping duties were imposed by the Central Government for five years vide Notification No. 67/2009-Customs dated 16th June, 2009.

5. WHEREAS, in terms of the Customs Tariff Act, 1975, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

6. AND, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

7. AND, WHEREAS, in terms of the above provisions, Bajaj Healthcare Limited (hereinafter referred to as the applicant or the petitioner) representing the Domestic Industry has approached the Authority with a duly substantiated application requesting for continuation of the antidumping duties in force imposed by the Central Government vide Notification No. 67/2009-customs dated 16th June, 2009. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on the import of the subject goods from China PR (hereinafter referred as the subject country) and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject country as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The applicant has further argued that expiry of the measure against the subject country would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The applicant also claims that revocation of anti-dumping measures would result in intensified injury to the domestic industry and, therefore, the duty is required to be continued for a further period of five years.

8. The application has been filed by Bajaj Healthcare Limited on behalf of the domestic producers of the subject goods in India. Further, Amoli Organics Pvt. Ltd. and Reckon Pharmachem Pvt. Ltd have supported the petition. As per the information available on record, the applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods and, therefore, constitutes the domestic industry within the meaning of the AD Rules and also satisfies the criteria of standing in terms of the Rules.

9. The Authority on the basis of prime facie evidence given by the applicant considered that initiation of sunset review proceedings in respect of the anti dumping duty in force on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duties to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duties were removed or varied or both.

10. Having satisfied itself on the basis of positive prima facie evidence of dumping and injury to the domestic industry given by the applicant, substantiating the need for a review, the Authority initiated the Sunset Review vide Notification No. 15/10/2014-DGAD dated 11th June 2014 in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

11. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to and inclusive of 15th day of June, 2015, vide Notification No.33/2014-Customs (ADD) dated 23.07.2014.

12. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

**B. PROCEDURE**

13. The procedure described below has been followed in this investigation:
- i) The Embassy of the subject country in New Delhi was intimated about the initiation of the investigation in accordance with Rules.
  - ii) The Authority provided access to the copies of the non-confidential versions of the application to the known exporters and the Embassy of the subject country and other interested parties in accordance with the Rules.
  - iii) The Authority forwarded copies of the public notice to the following known producers/exporters in the subject country and provided them opportunity to make their views known in writing within forty days thereof in accordance with the Rules:
    - (a) Baoji Oasier Bio-Tech Co. Ltd.
    - (b) The TNN Development Limited
    - (c) Ningbo Pharmacos International Trading Co. Ltd.
    - (d) Zhengzhou Biocaro Pharmaceutical & Health-Care Products Co. Ltd.
    - (e) Dalian Sinobio Chemistry Co. Ltd.
    - (f) Qingdao Dacon Trading Co., Ltd.
  - iv) No response or submission has been filed by any of the producers/exporters from the subject country.
  - v) China being a Non-Market Economy country, a Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to all the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation the normal value in China was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it examined the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the co-operative exporters/producers in that country. However, no response has been received from the producer/exporters from China PR in this regard.
  - vi) The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known importers/consumers/consumer associations (whose names and addresses were made available to the Authority) of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the prescribed time limit in accordance with the Rules.
    - a) Glaxo Smith Kline Pharmaceuticals Ltd.
    - b) Pfizer Ltd.
    - c) Global Exim.
    - d) Anglo French Drugs & Industries Limited.
    - e) Piramal Healthcare Ltd.
    - f) Ranbaxy Laboratories Ltd.
    - g) Dr.Reddy's Laboratories Ltd.
    - h) Meyer Organics Private Limited.
    - i) Vovantis Laboratories Private Limited.
    - j) Jain Irrigation Systems Limited.
    - k) Parle Agro Private Limited.
  - vii) The following importers responded to the importer questionnaire in response to the above notification:
    - a) Abbott Healthcare Pvt. Ltd., Mumbai.
    - b) Pfizer Ltd., Mumbai.

- viii) The following importers/ association submitted their legal submissions after the initiation:
- Piramal Enterprises Ltd., Mumbai.
  - Pride Drugs and Pharma Pvt Ltd, Ahmadabad.
  - Abbott Healthcare Pvt. Ltd.
  - OPPI (Organisation of Pharmaceutical Producers of India).
- ix) The period of investigation for the purpose of the present review is 1<sup>st</sup> October 2012 to 31<sup>st</sup> December 2013 (15 months). However, injury analysis covered the periods Apr'10-Mar'11, Apr'11-Mar'12, Apr'12-Mar'13 and the POI.
- x) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation. The import information provided by DGCI&S on transaction-wise basis has been adopted in this investigation.
- xi) Exporters, producers, importers and other interested parties, who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.
- xii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per the Rules.
- xiii) The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III to work out the cost of production and the non- injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti- dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiv) In accordance with the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 6th May, 2015. The parties presenting their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally.
- xv) The submissions made by the interested parties during the course of the investigation and the oral hearing, have been addressed in this investigation to the extent found relevant.
- xvi) Verification of the information and data submitted by the applicant was carried out to the extent deemed necessary.
- xvii) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xviii) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its views on the basis of the 'facts available' and treated such parties as non-cooperative.
- xix) A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which formed the basis of the Final Findings was issued to the all the interested parties on 02.06.2015. The post Disclosure Statement submissions have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.
- xx) \*\*\*\* in this Final Findings Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi) The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs. 58.05 = 1 US\$.

### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND 'LIKE ARTICLE'

#### Views of the Domestic Industry

14. The views of the domestic industry are as follows:
- The product considered in the present investigation is Vitamin- C in all its form and derivatives.
  - Vitamin C is also known by various synonyms such as ascorbic acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc.,as described under entry number '867 of Merck Index'.

- c) Vitamin-C is primarily used by the pharmaceuticals companies for production of various medicines. However, the product has significant uses in non-pharmaceutical industry also.
- d) Vitamin-C is an organic chemical. It is classified under customs sub-heading no. 2936.27 under the Customs Tariff Act. Complete classification of Chapter 29 in so far as it concerns imports of the product as per Customs Tariff Act is 29362700.
- e) The scope of the product under consideration remains the same as that of product in original investigations.

#### **Views of Interested Parties**

15. None of the opposing interested parties has made any submissions in this regard.

#### **Examination by the Authority**

- 16. The product under consideration in the present review investigation is Vitamin-C in all its form and derivatives, originating in or exported from China PR. Vitamin C is also known by various synonyms such as ascorbic acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-oxo L-Gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone etc., as described under entry number '867 of Merck Index'. Vitamin-C is primarily used by the pharmaceuticals companies for production of various medicines. However, the product has significant uses in non-pharmaceutical industry also. Vitamin-C is an organic chemical. It is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs sub-heading no. 29362700.
- 17. The Authority further notes that the product under consideration produced by the domestic industry is like article to the goods imported from the subject country. Product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules.
- 18. The Authority holds that the present investigation is a sunset review investigation and, therefore, the scope of the product under consideration remains the same as that of product in original investigations.

#### **D. STANDING AND SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY**

- 19. The petition was filed by M/s Bajaj Healthcare Ltd. as applicant domestic industry (hereafter referred to as the petitioner or the applicant).

#### **Views of the Other Interested Parties**

- 20. The opposing interested parties have contended that no information has been provided evidencing the actual production data of all known producers, including the supporters, i.e., M/s Amoli Organics and Reckon Pharmachem. There is no basis to conclude that the Petitioner actually constitutes major proportion of Indian production of the subject goods and is qualified to be determined as 'domestic industry'.

#### **Views of the Domestic industry**

- 21. The petition was filed by M/s Bajaj Healthcare Ltd. Apart from the petitioner, there are four other producers of the subject goods in India. Amoli Organics Pvt. Ltd. and Reckon Diagnostics Pvt. Ltd. have supported the petition. The production of the petitioner along with the supporters constitutes 88% of the total Indian production in the POI. On its own also, the production of the petitioner constitutes major proportion of the total Indian production in the POI and, therefore, the petitioner constitutes domestic industry. Further, in case of sunset review, standing is not required to be examined.

#### **Examination by the Authority**

- 22. As regards the argument that the production of petitioner may or may not constitute a major proportion in Indian production in the POI fixed by the Authority for detailed investigations and that no information has been provided evidencing the actual production data of all known producers, including the supporters, i.e., M/s Amoli Organics and Reckon Pharmachem, the Authority notes that the production of the petitioner alone constitutes 53% of the Indian production and in such a situation, there is no need to examine the data of the supporters for the purpose of determining standing of the petitioner as domestic industry. Therefore, the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the anti dumping Rules and also has standing under the Rules.

## E. MISCELLANEOUS ISSUES

### Views of the Opposing Interested Parties

23. The views of the opposing interested parties are as follows:
- a) Even after imposition of anti-dumping duty for 15 years, the applicant still contends that there has been no improvement in its performance. Thus, it is clear that the applicant has been suffering any alleged injury as a result of its own inefficiencies. In addition, the present positive performance of the applicant, which is evident from the improvement on all the key injury parameters, has resulted from its own strategic decisions such as increase in capital investments and capacity and is independent of the imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from China.
  - b) It is not in the larger interest of the public in the country that the anti-dumping duty be imposed on imports of Vitamin C as the increased cost due to imposition of the anti-dumping duty will have to be finally borne by the end-users that comprise the vast poor population requiring affordable essential medicines.
  - c) The user industry in India should not be penalized for the reluctance of the domestic industry to address structural issues existing therein since the last 15 years.
  - d) The applicant has argued that in spite of low volume of import of the PUC many foreign jurisdictions continue to levy anti dumping duty. The case laws cited by the applicant are of foreign jurisdictions and are not applicable in the present investigation. Secondly, the respondents would draw the attention of the DA towards the Sunset Review investigation against imports of White Cement from UAE and Iran, wherein low volume of imports was one of the major considerations for revocation of the anti-dumping duty.
  - e) As per the new DPCO order of May 2013, drug formulation manufacturers are bound by the maximum retail price but bulk drug manufacturing companies are not bound. Extension of anti-dumping duty for another five years on bulk drug Vitamin C would severally prejudice the objective of making Vitamin C drug available at affordable prices, as manufacturing of drug formulations in India would become unviable.
  - f) The applicant has claimed that Chinese exporters of Vitamin C have been found guilty of forming cartel and fixing prices by a US court. The purpose behind forming a cartel is to exploit a market by fixing higher prices. In fact as per the article provided by the applicant, the monopoly by Chinese manufacturers has resulted in increasing the prices by more than 200%. Thus, if this is the case, then the argument of the applicant with respect to continued import of low priced import from China automatically gets rejected. Further this event has occurred in US and the applicant has not provided any evidence as to whether a similar practice is being followed in India or not. Even if such a practice is being followed, the remedy lies before the Competition Commission of India and not before DGAD.
  - g) The issue of monopolistic behavior of Chinese exporters does not come within the ambit of anti-dumping laws. Further, any company having a monopoly over a market would look to exploit the market by charging higher prices and not lower prices.
  - h) Complete and updated information for revised POI and the injury period has not been made available to interested parties even after mandated period of 40 days since the initiation of the investigation has elapsed.
  - i) Data for the present period which forms part of the POI cannot be kept confidential and, therefore, analysis of both dumping and injury remains deficient for the purposes of initiation.
  - j) The Authority cannot request the interested parties to file the data for the POI, when the DA has not provided this data which has been considered in the present POI as accurate and adequate.
  - k) The applicant has misconstrued the relevant provisions in contending that the Authority must compulsorily initiate a sunset review investigation. A sunset review may be initiated only if an interested party submits a request with “positive information substantiating the need for a review” or if the Authority determines that “good and sufficient grounds exists” for self-initiating a review. The application filed by the applicant does not contain “positive information substantiating the need for a review”.
  - l) There is a gap of almost 6 months from the end of the POI and the date of initiation. The POI must end as close to the date of initiation as possible. Further, the application submitted prior to initiation was only for the period October 2012 – September 2013, while the POI extends from October 2012 until December 2013. Effectively, the gap between the data provided by the applicant and the initiation of the investigation was 9 months and the Authority still proceeded to initiate the investigation. The applicant submitted the data for the period from October 2012 until December 2013 only on August 21, 2014, post-initiation of the investigation.

- m) Initiation of the instant investigation is bad in law, as incomplete data which fails to cover the POI cannot be considered to constitute “positive information substantiating the need for a review” within the meaning of Article 11.2 of the WTO ADA and 23(1A) of the Indian AD Rules. Submission of positive information substantiating the need for a review by an interested party is a pre-condition for the initiation of any review. In the absence of such information at the time of initiation, the Authority is not permitted under the law to initiate the review.
- n) Preference of imported product over domestic product is in view of un-quantified quality differences.

### **Views of the Domestic Industry**

24. The views of domestic industry are as follows:

- a) The Act and the Rules do not prescribe any time limit beyond which the anti-dumping duty should not be extended. The legal provision states that the anti-dumping duty can be extended further from time to time, if it is found that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty.
- b) As regards the argument that the imposition of anti dumping duty shall be against public interests, there has been no material adverse effect on the consumers because of anti-dumping duty imposed in the past. Further, none of the interested parties have provided any information to establish that imposition of anti-dumping duty shall have significant adverse effect on public at large.
- c) The objective of anti-dumping duty is to prevent dumping causing injury to the domestic industry in India and not penalizing consumers.
- d) The petitioner has provided data for the POI fixed by the Authority and a non-confidential copy of the same was also submitted to be placed in the public file.
- e) Petition for the POI fixed by the Authority is not a necessary precondition for the interested parties to file questionnaire response and other information for the POI fixed by the Authority.

### **Examination by the Authority**

25. With regard to the various contentions of the interested parties, the Authority notes as follows:

- a) With regard to the contention raised by the opposing parties that there is no case of anti-dumping duty in India beyond 15 years and duty should not be extended; the Authority holds that the Act and the Rules do not prescribe any time limit beyond which the anti-dumping duty should not be extended. Section 9A(5) clearly provides that the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, in which case the Central Govt. may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years. Thus, the legal provision clearly states that the anti dumping duty can be extended further from time to time, if it is found that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. The petition filed by the domestic industry contained sufficient information on dumping and consequent injury which was examined by the Authority before initiation of investigation and, on being *prima facie* satisfied, the Authority had initiated the investigation.
- b) The Authority further notes that in a sunset review investigation, anti-dumping duty is required to be imposed so long as the investigation shows that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- c) As regards the argument that the imposition of anti-dumping duty shall be against public interests, the Authority notes that none of the interested parties has provided any information to establish that imposition of anti dumping duty shall have significant adverse effect on public at large. On the contrary, the domestic industry claimed that there has been no material adverse effect on the consumers because of anti-dumping duty imposed in the past. The Authority also notes that the purpose of anti-dumping duty is to address the unfair practice of dumping causing injury to the domestic industry.
- d) As regards anti-dumping duty penalizing consumers for long period, the Authority considers that anti dumping duty is not to penalize any party. The objective of anti-dumping duty is preventing dumping causing injury to the domestic industry in India. It is also noted that none of the parties has quantified how imposition of anti-dumping duty has caused or is likely to cause any adverse effect on the consumers.
- e) As regards the submissions of domestic industry and interested parties concerning low volume of imports and extension of anti-dumping duty in such situations, the Authority considers that the issue is not relevant in the present case, as the volume of imports in the present case is quite significant.

- f) As regards applicability of DPCO, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is to provide level playing field to the producers of the product. It is also noted that the consumers have not established how continuation of anti-dumping duty for another five years on Vitamin C would severely prejudice the objective of making Vitamin C drug available at affordable prices and how manufacturing of drug formulations in India would become unviable. In any case, as per Price Drug Control Order of May, 2013, Vitamin C (bulk drug) is not covered under the DPCO order. It was covered before May, 2013.
- g) As regards submissions of domestic industry and interested parties concerning cartelization and court cases outside India, the Authority considers that the same is beyond the purview of present investigation. The Authority has considered the price at which goods have been imported into India from China and the prices at which goods have been exported from China to other countries.
- h) The petition was filed considering October 2012 to September 2013 as the investigation period. The Authority initiated the investigation considering October 2012 to December 2013 as the investigation period in order to allow the Authority to adopt most recent period. The petitioner has provided data for the POI fixed by the Authority and a copy of the same was placed in the public file, which was accessed by interested parties during the course of the proceedings.
- i) As regards confidentiality claims, the Authority has considered confidentiality claims made by parties and has allowed the same considering the confidentiality provisions under the law, the claims made by the domestic industry and past practices of the Authority. The Authority holds that the claims made by the domestic industry in this regard are consistent with the past practices of the Authority.
- j) The Authority considers that the POI in the petition need not be the period for which the Authority should conduct investigations. Further, the Authority considers that petition for the POI fixed by the Authority is not a necessary precondition for the interested parties to file questionnaire response and other information for the POI fixed by the Authority. At the stage of initiation, the Authority has asked all the interested parties to provide information for the POI fixed by the Authority. All information filed before the Authority has been placed in the public file to enable opposing parties to defend their interest. The Authority considers that absence of petition for POI fixed by the Authority cannot prevent the interested parties from filing their responses for the POI fixed by the Authority.
- k) As regards submissions of the domestic industry and interested parties with regard to compulsory initiation of sunset review investigation, the Authority considers that the present investigation has been initiated on the basis of duly documented petition.
- l) As regards submissions concerning confidentiality of information and non-disclosure of costing information, evidence relating to normal value, import data for raw materials and evidences relating to export price, the Authority notes that the claims made by the domestic industry are consistent with the practice being followed by the Authority in this regard. Further, petitioner has made available evidence of raw material prices and evidence with regard to export price in their rejoinder submissions which has been placed in public file and has been made available to all interested parties.
- m) As regards submissions concerning unacceptable quality and rejection of material, the Authority notes that the domestic industry has produced and supplied the product for all those applications where imported product has been used. Petitioner provided information, duly certified by a Chartered Accountant showing that it has supplied 150,600 kgs. of material to M/s. Piramal Enterprises Ltd/ Piramal Healthcare Pvt Ltd., out of that 500 kgs of material was rejected. Further, for the rejected material, the company has not been paid sales consideration. The Authority also notes that preference of imported product over domestic product in view of alleged un-quantified quality differences cannot establish that the goods produced and supplied by the domestic industry are not like articles to the product under consideration. The rules require the Authority to consider whether goods supplied by the domestic industry are like article to the imported product. It is also submitted that the CESTAT has held in the matter of DSM Idemitsu Limited v. Designated Authority, reported in 2000 (119) E.L.T. 308 that the difference in quality between imported and domestic product does not imply that the domestic product is not a like article to the imported product.
- n) The Authority has also noted that there is no evidence on record before the Authority that the plant of the domestic industry near Vadodara in Gujarat where Vitamin-C is being manufactured was shut down by any Government body because of violation of pollution norms.
- o) The Authority has also noted that there is no evidence on record before the Authority that EU and USA have put any anti-dumping duty on the imports of the subject goods.

**F. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AND PARAMETRS****Determination of Dumping**

26. The Authority notes that none of the exporters/producers from China PR has responded to the initiation notification by filing exporter questionnaire in the manner and format prescribed.

**Views of other interested parties**

27. The opposing interested parties have contended that the method for determination of normal value is flawed as (a) India is not an appropriate analogue country for China, (b) the scale of operations of producers in China is much larger as compared to producers in India resulting in lower cost of production in China, and, (c) producers of Vitamin C in India import 2 Keto L Gulonic Acid, which is the main raw material used for production of the subject goods from China, whereas Chinese producers manufacture and use 2 Keto L Gulonic Acid captively and save incremental cost related to procurement etc.
28. Normal value constructed based on United Kingdom's export price to India is impermissible as United Kingdom is not an appropriate analogue market economy third country as compensation cost, electricity cost and raw material cost in United Kingdom is far higher than in China.
29. The applicant is not at liberty to suddenly change the data set from IBIS to DGCI&S. Further, any choice on the Authority's part to select DGCI&S data simply because such data is more favourable to the applicant's interests would constitute violation of due process norms and principles of natural justice.

**Views of the Domestic industry**

30. It has been contended by the domestic industry that China PR should be treated as a non-market economy country, *inter alia*, stating that:
- a) Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity: The European Commission has consistently held that possibilities of State interference cannot be ruled out in cases where there is significant share of a State owned/controlled entity. It is not only the question of past interferences alone but also possibilities of potential State interference in the future after the imposition of anti-dumping duties that is relevant for granting market economy treatment.
  - b) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values. The Domestic industry contends that "substantially reflect market values" has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market. The Domestic Industry contends that the fact that such prices are comparable to the price prevailing in China PR is grossly insufficient.
  - c) Major inputs include utilities: The Domestic industry contends that production of the product concerned requires power and fuel as a major item of utility. Admittedly, while the power supplier is a State owned entity, insufficient information is available with regard to fuel supplier. It has not been established by the exporters that the prices of utilities reflect fair market values.
  - d) Market economy status cannot be given unless the responding exporters establish that their books are audited in line with international accounting standards: The domestic industry contends that Chinese exporters have repeatedly disputed the treatment of European Commission to reject market economy treatment in such situations where Chinese exporters are unable to establish that their books are consistent with Chinese GAAP. Chinese companies in such cases have been contending that the requirement of insisting on compliance with International Accounting Standards is beyond law. The European Commission has held that the requirement on insisting compliance with International Accounting Standards is to ensure accuracy and adequacy of revenues and expenses, assets and liabilities expressed in the annual report. To quote the European Commission, reliability of the accounts is not established with regard to this aspect unless the books are consistent with International Accounting Standards.
  - e) Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied: The Domestic industry contends that the European Commission has repeatedly insisted that market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the Rules.
  - f) Onus/obligations: The Domestic Industry contends that it is not for the Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.

- g) Transformation: The Domestic Industry contends that in a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- h) Response from group as a whole: The Domestic Industry contends that market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected, regardless of the fact whether or not the other companies of the group are involved in production or sale of the product under consideration.
- i) Failure to satisfy a number of conditions mentioned above by the responding Chinese exporters is sufficient to hold that market economy status cannot be granted to responding Chinese companies and, thus, the Normal value should be determined in accordance with the Rules.
- j) None of the Chinese exporters has responded to the exporter's questionnaire response or claimed market economy treatment in the present case.
- k) Further, Normal Value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not available to the petitioner.
- l) Export price from other countries to India cannot be adopted for the reason that import price from other countries could be affected due to imports from subject country.
- m) Petitioner has claimed determination of normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

#### **Examination of Market Economy Treatment claims in respect of China PR by the Authority**

31. Para 7 of Annexure I of the Rule provides that:

*"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner [keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question] and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

32. Further, the relevant provisions laid down under Annexure I to the Antidumping Rules are as follows:

*8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3).*

*(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three year period preceding the investigation is a nonmarket economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).*

*(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*

*(a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*

*(b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*

(c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and

(d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph".

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti dumping investigations, by a country which is a member of the World Trade Organization."

33. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules.
34. The Authority notes that none of the producers/exporters of the subject goods from China PR has submitted either questionnaire response or response to the market economy questionnaire consequent upon the initiation notice issued by the Authority or has sought to rebut the non-market economy presumption.
35. In view of the same the Authority has determined the normal value for China PR as per the relevant Rules on the basis of best available information.

#### **Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR**

36. As regards the argument of the other interested parties that Normal value constructed based on United Kingdom's export price to India is impermissible as United Kingdom is not an appropriate analogue market economy third country, the Authority notes that it has not constructed the normal value based on the data of UK. As regards the argument of the other interested parties that determination of normal value on the basis of cost of production is inappropriate, the Authority considered all available information on record. It was found that import price from third countries to India was an option available with the Authority for determining normal value. This would have, however, significantly increased the dumping margin. The petitioner in fact has submitted that the Authority should consider import price from other countries to India for determination of normal value. The Authority, therefore, considers that the methodology adopted is at the least more favourable to the exporters and consumers. It is also noted that none of the Chinese producers has made any quantified claim in this regard. It is further noted that none of the producers and exporters of the subject goods from the subject country has rebutted the non-market economy presumption.
37. As regards the contention that in view of production process and technology difference between Chinese producers and Indian producers, the normal value should be determined based on price constructed in a market economy third country and such price should be based on export price from China to EU, the Authority holds that Para 7 of Annexure-1 provides a number of alternate methodologies and the same does not include price from such non market economy country to other countries. In fact, if normal value based on cost or price in China cannot be adopted for the reasons specified in Para-7 and 8, it follows that price from China to Europe can also not be adopted.
38. In view of the above position and in absence of rebuttal of non-market economy presumption by the respondent Chinese company, the Authority considers it appropriate to proceed with para-7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR. As none of the producers/exporters from China PR has submitted MET questionnaire response, the Authority is unable to grant market economy status to Chinese producers in general for the purpose of determination.
39. The Authority has determined normal value having regard to para-7 of Annexure-I for the purpose of present investigation. The normal value for the subject products imported from China PR into India has been constructed considering consumption of major raw materials as per information provided by the domestic industry, international prices for major raw materials, conversion cost, interest, SGA etc. at the levels allowed for the domestic industry. 5% of cost of sales excluding interest has been allowed towards reasonable profit. The Normal Value so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

### **Determination of Export Price for producers and exporters in China PR**

40. Since none of the exporters from any of the subject country has responded to the Authority, the Authority has determined Export Price in respect of imports from China PR on the basis of best information available in accordance with the Rules. The petitioner has claimed export price on the basis of imports of the product under consideration in India, as reported in IBIS transaction-wise import data. The Designated Authority has also procured the transaction wise import data from the DGCIS. The Designated Authority has considered the data received from DGCI&S as per its practice in a large number of investigations and determined the export price considering all imports of the product under consideration in India. Thus, there is no sudden change from IBIS data to DGCIS data. Price adjustments have been made on the basis of claims made by petitioner domestic industry in view of non cooperation from the exporters from China PR. The Export Price so determined is as indicated in the Dumping Margin Table below.

#### **Dumping Margin**

41. Considering the normal value and export price as determined above, dumping margins have been determined as follows. It is seen that the dumping margins are more than de-minimis and significant.

Normal Value	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin range
US\$/kg	US\$/kg	US\$/kg	%	%
***	***	***	***	110-140

## **G. INJURY AND CAUSAL LINK DETERMINATION**

#### **Views of the opposing interested parties**

42. The views of the opposing interested parties with respect to injury and causal link are as follows:
- a) Domestic manufacturers are still importing final stage intermediate product 2-Ketogluconic Acid from China in order to manufacture the PUC. Due to the volatility in the prices of the raw material and in the exchange rates, the domestic manufacturers have suffered losses on account of import of this intermediate product. The Indian currency depreciated by about 20% during the period 2011-12 to 2012-13 and resulted in imports becoming expensive. This argument is supported by the reports of rating agencies for Reckon with respect to PUC.
  - b) Chinese exporters are more cost competitive as compared to Indian domestic manufacturers. This position is supported by the statement of Mr. Manish Doshi, Managing Director of Amoli Organics (2012): "In terms of engineering and chemistry, unfortunately the Chinese pharmaceutical industry fares better than the Indian pharmaceutical industry.....Chinese pharmaceutical industry is quite cost competitive as they are quite efficient."
  - c) The data provided by the applicant does not establish that it has suffered material injury nor does it establish that there is a case of recurrence of material injury upon revocation of the anti dumping duty.
    - i) There is no absolute increase in the volume of imports from the subject country.
    - ii) The demand increased by 8%, production of DI by 37%. On the other hand, import during the same period declined by 11%.
    - iii) There has been an increase in the installed capacity and production. There is no decline in capacity utilization of the applicant.
    - iv) The domestic sales volume and value of the applicant have also increased.
    - v) Market share of the applicant has also increased.
    - vi) The decline in selling price of the domestic industry is on account of reduction in the maximum selling price for the product under consideration by NPPA before May 2013.
    - vii) In the support letter Reckon has stated that it has discontinued production of Vitamin C due to cheap imports. However, as per publicly available data, Reckon's revenue and earnings increased in 2011-12 as compared to 2008-09. As per the report, the negative aspects for Reckon were unfavorable changes in regulatory pricing, volatility in the price of the raw material which is imported and high product concentration risk as it is only involved in the production of the PUC.

- viii) If Reckon, which is only producing the PUC, can increase its revenue growth and have a very healthy operating EBITDA, the applicant which is also operating in the same industry environment should not be incurring losses.
- ix) In view of the above, there is no causal link between the imports of PUC and the claim of material injury by the applicant.
- d) The injury data in the present investigation has been provided only for Bajaj Healthcare Ltd. The applicant should have provided injury related data for at least the domestic producers supporting the application, which it claims taken together, constitute 88% of total domestic production.
- e) There has been a decrease in the volume of imports from the subject country over the course of the injury investigation period and the POI in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- f) There is lack of injury based on economic parameters relating to the applicant as the applicant's performance has improved significantly in terms of capacity, production, capacity utilization, sales, market share, inventory, productivity, wages, salaries and employment.
- g) Further, as four of the domestic producers have refrained from providing cost and injury related data in the present investigation, we submit that the Authority is not in a position to assess whether domestic producers of the subject goods are suffering any injury as per the requirements of Article 3.1 of the WTO ADA.
- h) In the previous review, there were only two domestic producers of the subject goods. At present, there are five domestic producers of the subject goods. The domestic industry is most definitely showing a positive growth. New players would not enter a market that is suffering injury or is not considered profitable.
- i) The extent of injury caused by the significant increase in expenses of the applicant must be segregated from the any injurious effect caused by imports.
- j) No price suppression or depression has been caused by imports from the subject country as there has been a decrease in the selling price as well as the cost of production. The decrease in the cost of sales is as a result of the decrease in the price of 2 Keto L Gulonic Acid. Therefore, the imports have not depressed prices to a significant degree or prevented price increases, which otherwise would have occurred.
- k) The maximum selling price of Vitamin C has been regulated by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) and any upward trend in prices of the domestic industry has been subject to a ceiling imposed by the NPPA.
- l) The selling price of the applicant has been above its cost of production and, therefore, the applicant should not be suffering any losses and is not facing any price suppression. Further, other domestic producers of the subject goods have increased their selling prices in the most recent period.
- m) The application itself shows clearly that certain expenses incurred by the applicant such as depreciation, wages and interest were responsible for any losses rather than imports of the subject goods. The decline in the profits and return on investment is linked to the increase in the aforesaid expenses of the applicant. The return on investment and profits turned negative in 2012-13 during the period when the depreciation increased by 98%, wages and salary by 58% and interest by 11% as compared to the base year. In addition, in the following year, the wages and salary as well as interest increased by a further 23% as compared to the previous year. An increase of nearly 100% in the depreciation as well as wages and salaries of the Applicant was bound to impact the profits and return on investment.
- n) The figures cited by domestic industry with respect to volume of imports, price undercutting, domestic sales, profits, and market share in demand (including and excluding captive) among others, do not match with the figures cited in their petition or in the updated annexures provided to the other interested parties.
- o) The reason for the decrease in the cash profits of the applicant is due to an increase in investments. In particular, the applicant appears to be incurring a gross profit but as a result of the increase in its investments, there has been a decline in its cash profits.

#### **Views of the Domestic Industry**

43. The domestic industry, in its submissions has, inter-alia, argued as follows:
  - a. Despite the presence of anti-dumping duties, significant volume of subject imports is entering India at dumped prices. This has been because of absorption of anti dumping duty by Chinese suppliers. Further, exports of the product from China as per China customs data in fact show significantly higher exports of the product to India.
  - b. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

- c. The landed price of imports is not only below the selling price of the domestic industry but also below the cost of production and non-injurious price of the domestic industry.
- d. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.
- e. Imports are depressing the prices of the domestic industry. There has been very significant decline in import prices, despite significant appreciation of US\$, which has forced the domestic industry to reduce the prices.
- f. Increase in production and sales volumes is only because domestic industry tried to combat the low prices offered by the Chinese producers.
- g. Performance of the domestic industry has deteriorated drastically in terms of profits, return on investments, cash flow. Profitability and return on investment has become negative since 2012-13, whereas cash profits have declined significantly over the injury period.
- h. Growth of the domestic industry is adverse in terms of price parameters.
- i. Production from 2-Ketogluconic Acid to Vitamin-C constitutes production of the product. Further, volatility of the raw material prices or exchange rates is expected to impact the price of both the raw materials and finished product. It is not established how these changes could selectively impact profitability of the product alone. In fact, given positive value addition from 2-Ketogluconic Acid to Vitamin-C, depreciation of Indian currency should have helped domestic industry in improving its profitability.
- j. The statement of the Managing Director in Annual Report is with reference to the difference in performance of Indian industry vis-à-vis Chinese industry. The statements made in the Annual Report are not responsible for the claimed deterioration in performance of the domestic industry.

#### **Examination by the Authority**

- 44. The Authority has considered various arguments put forth by various interested parties in their submissions and issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority. On the basis of data and information available, the Authority concludes that the current dumping margins from the subject country are above *de minimis* level. The Authority, therefore, proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country.
- 45. With regard to the various contentions of the interested parties, the Authority observes as follows:
  - a) As regards the argument concerning imports of 2-Ketogluconic Acid, volatility of prices of raw materials and exchange rate, the Authority notes that production from 2-Ketogluconic Acid to Vitamin-C constitutes production of the product. Further, volatility of the raw material prices or exchange rates is expected to impact the price of both the raw materials and finished product. It is not established how these changes could selectively impact profitability of the product alone. In fact, given positive value addition from 2-Ketogluconic Acid to Vitamin-C, depreciation of Indian currency should have helped domestic industry in improving its profitability.
  - b) As regards relative competitiveness of Chinese and Indian producers, the Authority notes that the argument is not substantiated. It is not established how this relative competitiveness is responsible for deterioration in performance of the domestic industry over the injury period. The Authority for the purpose of analyzing injury is required to focus on improvement or deterioration in the performance of the domestic industry over the injury period. The Authority is not required to compare domestic industry with exporters while concluding on injury.
  - c) As regards injury data from other domestic producers, the Authority clarifies that no other domestic producer has provided information to the Authority for treatment of such producers as a domestic industry. However, since Bajaj Healthcare alone has major proportion of the total production of the subject goods and thus constitutes as the domestic industry, there is no need to examine the costing/injury data of the other producers. This practice has been followed by the Authority in past cases also.
  - d) As regards the argument that imports of the product declined in POI, the Authority notes that imports of the product are quite significant in absolute terms and in relation to production and consumption. Further, the Authority notes the argument of the domestic industry that exports of the product from China as per China customs data in fact shows significantly higher exports of the product to India. It is also noted that the import volumes considered in the petition based on secondary sources show lower volume imports as compared to imports reported in the DGCI&S.
  - e) As regards the argument that absence of data from supporting domestic producers has prevented the interested parties from offering comments, the Authority notes that the injury to the domestic industry is required to be seen for the defined domestic industry.

- f) As regards argument that there is increase in number of domestic producers of the product, the Authority notes that the same does not imply that cessation of duty is unlikely to lead to dumping and consequent injury to the domestic industry.
  - g) As regards the argument that there is significant increase in expenses incurred by the domestic industry, the Authority has examined and verified the data before adopting the same for the present determination.
  - h) As regards the argument that injury to the domestic industry is because of increase in depreciation, wages and interest, the Authority examined the data and found that the decline in profitability is not on account of increases in these parameters.
46. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... Taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to suppress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
47. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with the rules supra.
48. The present investigation is a sunset review of anti dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis basis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry considering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. The Authority has examined whether existing measure is not sufficient to counteract the dumping which is causing injury.
49. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, in which case, the Central Govt. may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension.
50. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has examined injury to the domestic industry by considering information relating to M/s Bajaj Healthcare Ltd., constituting domestic industry under the Rules.
51. The Authority has considered the views of all the interested parties and addressed the same appropriately. The Authority has analyzed injury parameters in accordance with the rules. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been treated confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. Accordingly, the volume and price effect of dumped imports have been examined as follows:

#### **Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry**

52. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows:

#### **Demand and Market Share**

53. The Authority has considered the transaction-wise import data procured from DGCI&S for the assessment of total volume and value of imports from the subject country and other countries. The position with regard to demand and market share is as follows –

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
Demand (excluding captive)	MT	2706	2903	3121	2807
Demand (including captive)	MT	2745	2945	3158	2893
Sales of Domestic industry (excluding captive)	MT	807	919	1087	1077
Sales of Domestic industry (including captive)	MT	846	962	1123	1163
Sales of other Indian producers	MT	1,143	1,173	1,256	1,056
Imports – China	MT	653	680	674	556
Imports – Other countries	MT	103	131	105	118
Market share in Demand (excluding captive)					
Domestic Industry	%	29.83%	31.66%	34.81%	38.36%
Other Indian Producers	%	42.23%	40.40%	40.23%	37.62%
Imports – China	%	24.13%	23.43%	21.60%	19.81%
Other countries	%	3.81%	4.51%	3.36%	4.21%
Market share in Demand (including captive)					
Domestic industry	%	30.82%	32.65%	35.56%	40.19%
Other Indian Producers	%	41.64%	39.81%	39.77%	36.50%
Imports – China	%	23.79%	23.09%	21.34%	19.22%
Other countries	%	3.75%	4.45%	3.33%	4.09%

54. It is seen that the demand for the product has increased upto 2012-13 and then declined in the POI. However, the demand shows slight increase in the POI when compared to the base year. Sales volumes of the domestic industry have increased over the injury period. Imports from the subject country increased up to 2012-13 in comparison to the base year and then declined in the POI. The Authority notes that imports from the subject country have remained significant in spite of anti dumping duty being in place.

#### **Import volumes and share of subject country:**

55. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

*“While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India”*

56. The import volumes for the injury period, considering the transaction wise data provided by DGCI&S are as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
China PR	MT	653	680	674	556
Other countries	MT	103	131	105	118
Total imports	MT	756	811	779	674
Dumped imports in relation to:					
<input type="checkbox"/> Total Imports	%	86.37%	83.82%	86.53%	82.44%
<input type="checkbox"/> Production	%	32%	32%	28%	25%

57. The Authority notes that imports from China PR have remained significant in absolute terms as well as in relation to consumption and production in the country in spite of anti dumping duty being in place.

58. Since the present investigation is a sunset review investigation, the present volume of imports is required to be seen in the light of likelihood of injury to the domestic industry.
59. As regards the argument that the market share of the domestic industry has increased and that of China has declined, the Authority holds that the performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of parameters such as profits, cash flow and return on investment. Further, since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority is required to analyze not only continued injury but also likelihood of injury in the event of cessation of anti dumping duty.

#### **Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry**

60. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

*“With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree.”*

61. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined by the Authority with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

#### **Price undercutting and underselling effects**

62. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
63. Price undercutting has been determined by comparing the landed value of dumped imports from the subject country over the entire period of investigation with the net sales realization of the domestic industry for the same period. For this purpose, landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the value reported in the DGCI&S data of import prices from the subject country. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been deducted.
64. For the purpose of price underselling determination, the landed price of imports from the subject country has been compared with the Non-injurious Price of the domestic industry determined for the POI.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
Landed Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	83	70	66
Net Sales Realization	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	84	76	76
Price Undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting Range					30-60
Non-injurious Price	Rs./Kg				***
Price Underselling	Rs./Kg				***
Price Underselling	%				***
Price Underselling Range	%				100-120

65. In this regard, Authority notes as under:
- The landed value of imports from the subject country is materially below the selling price of domestic industry signifying significant positive price undercutting.
  - A comparison has also been made between the landed price of imports and Non Injurious Price. It is noted that the landed price of imports from the subject country is far lower than the non injurious price in the POI.
66. The Authority thus concludes that the landed value of imports from the subject country caused significant price undercutting as well as price underselling.

**Price suppression and depression effects of the dumped imports:**

67. The price suppression effects of the dumped imports have also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject country.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualised)
Landed price of imports	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	70	66
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	99	98
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	76	76

68. It is noted that the landed price of imports is substantially below the cost of sales and selling price of the Domestic Industry in the POI. Whereas cost of sales has been more or less stable over the injury period, the NSR has substantially declined to keep pace with the landed price. The imports are, thus, depressing the prices in the market.
69. The petitioner has claimed that in the event of cessation of current anti-dumping duty and if Domestic Industry chooses to sell at import prices, the Domestic Industry would suffer significant financial losses. The return on investment and cash profit would also be significantly negative.
70. As regards the contention that there is no suppressing or depressing effect of the prices of the domestic industry, the Authority holds that the selling price declined over the injury period, which cannot be considered insignificant. It is noted that whereas cost of sales remained more or less at the same level, the selling price and import price declined. It is, thus, clear that there was significant decline in selling price over the period, which was in response to decline in import prices.

**Examination of Economic Parameters Relating to the Domestic Industry**

71. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. However, the present investigations being a sunset review investigation, injury to the domestic industry is required to be assessed on mutates mutandis basis. Further, the Authority has examined whether existing measure has been sufficient to counteract the dumping which is causing injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

**Production, Capacity and Capacity Utilization, Sales of the Domestic Industry**

72. Based on the verified data, the information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualised)
Capacity	MT	960	1,200	1,320	1,320
Production	MT	865	955	1,140	1,177
Capacity Utilization	%	90%	80%	86%	89%
Sales of DI (In. Captive)	MT	846	962	1123	1163
Sales of DI (Ex. Captive)	MT	807	919	1087	1077

73. Based upon the above data, the Authority notes that –

- a) The domestic industry has enhanced its capacity in anticipation of increased demand and sales.
- b) The sales volume of the domestic industry has increased over the injury period.
- c) Production and capacity utilization of the domestic industry has also increased in the POI as compared to the base year.
- d) The domestic industry has not suffered injury in the form of sales volumes. However, the performance of the domestic industry has steeply deteriorated in respect of parameters such as profits, cash flow and return on investment as seen in the table below. Further, since the present investigation is a sunset review investigation, the Authority is required to analyze not only continued injury but also likelihood of injury in the event of cessation of anti dumping duty.

#### **Profitability, return on investment and cash profits**

74. Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry has been examined as under:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	99	98
Selling Price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	76	76
Profit/loss	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	10	-31	-26
Profit/loss	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	11	-42	-34
Profit before interest	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	26	-12	-2
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	34	5	6
Return on Investment	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	16	-8	-2

75. The Authority notes that the profitability of the domestic industry in terms of PBIT, cash profit and ROI has declined significantly over the injury period.

### **Inventories**

76. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
Stock (Volume) Average	MT	***	***	***	***

77. It is seen from the above information that inventories with the domestic industry increased over the injury period.

### **Employment and wages**

78. The Authority notes that the number of employees has increased over the injury period. It is noted that the wages paid by the domestic industry have also increased.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
Employment	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	108	110
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	158	171

### **Productivity**

79. Productivity of the domestic industry has been measured in terms of its labour productivity and per day productivity of the output and the Authority concludes that the productivity has increased commensurate to increase in production.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
Productivity Per Employee	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	123	124
Productivity Per Day	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	132	136

### **Factors affecting domestic prices**

80. Consideration of the import prices from the subject country and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market would show that the landed value of imported material from the subject country is significantly below the selling price of the domestic industry, causing severe price undercutting in the Indian market. There is no viable substitute to this product. It is also noted that demand for the subject goods has shown significant increase and this could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, the major factors responsible for the domestic industry prices are the landed prices of the imports and the cost of production of the domestic industry.

### **Magnitude of Dumping Margin**

81. The Authority notes that the dumping margin of the imports of the subject goods from the subject country is positive and substantial.

### **Growth**

82. On examination of various economic parameters of the domestic industry, the Authority notes that on a year by year basis the domestic industry has suffered adverse growth in terms of production, capacity utilization and sales; the

profitability has declined as can be seen from parameters such as profits, cash profits and return on investments. Considering the prices at which the exporters in the subject country are dumping the material in the Indian market; revocation of anti dumping duty would only lead to surge in the volume of dumped imports causing further deterioration in growth.

Growth percent (year by year)	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI (annualized)
Production	%	-	9%	16%	3%
Sales Volume	%	-	12%	15%	-1%
Selling Price	%	-	-20%	-11%	0%
Profit Rs.Laks	%	-	-89%	-476%	5%
Return on Investment	%	-	-83%	-151%	-25%
Capacity Utilization	%	-	-12%	8%	3%

#### **Ability to raise Capital Investment**

83. The Authority notes that the domestic industry has suffered financial losses in the POI. The petitioner has claimed that any fresh investment in such a situation is infeasible.

#### **Overall assessment of Injury**

84. The investigation has thus shown that the volume of dumped imports has remained significant, both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices, there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, and the effect of such imports was to depress prices to a significant degree. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in terms of parameters such as profits, cash profits and return on investment. The investigation has thus shown that the domestic industry has suffered continued injury.

#### **Causal Link**

85. As per the AD Rules, the Designated Authority is, inter alia, required to examine any known factors other than dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It was examined whether these other parameters listed under the Rules could have contributed to injury to the domestic industry.

##### **a. Imports from other countries and other Known Factors**

86. Imports of product under consideration from other countries are either below de minimis volume or at higher prices. Therefore, imports from other countries are not causing injury to the domestic industry.

##### **b. Contraction in demand**

87. The data shows demand of the product under consideration has increased up to 2012-13 and then declined in the POI. However, the demand in the POI has increased as compared to the base year. Therefore, decline in demand cannot be considered as the factor that could have impacted the performance of the domestic industry.

##### **c. Change in pattern of consumption**

88. No significant change in the pattern of consumption has come to the knowledge of the Authority, nor has any interested party made any submission in this regard.

##### **d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

89. The subject goods are freely importable. No trade restrictive practices in the domestic market have been brought to the knowledge of the Authority. The domestic producers compete with each other and at the same time with the subject

goods. The price of the domestic industry is influenced by the landed price of subject goods. The landed price of imports from subject country is below the selling price of the domestic industry. There is no evidence on record that the inter-se competition between the domestic producers increased/changed to such a significant extent that the injury to the domestic industry is on account of this inter-se competition.

e. **Development of technology**

90. The investigation has not shown any significant development in technology which could have caused injury to the domestic industry.

f. **Exports by the domestic industry**

91. The petitioner exports the product under consideration. However, exports form a very insignificant portion of total sales. Further, data relating to domestic sales only has been taken into consideration for assessment of injury to the extent possible.

g. **Productivity**

92. The Authority notes that productivity of the domestic industry has increased over the injury period. Therefore, decline in the productivity of the domestic industry could not be a cause of injury to the domestic industry.
93. The Authority, therefore, concludes that the other listed and known parameters have not caused injury to the domestic industry.

## **H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**

**Submissions by the Domestic Industry**

94. The domestic industry submitted as under in support of its claim of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- (a) The volume of imports from the subject country is significant and the dumping margin is also significantly high.
  - (b) The imports have increased significantly since inception. There has been significant increase in volume of imports between original investigation period and subsequent investigations periods.
  - (c) The imports from China would severely undercut the domestic prices in case anti dumping duty ceases.
  - (d) The volumes of imports from the subject country are likely to increase in the event of cessation of ADD for the following reasons –
    - i) Dumping margins in the previous sunset review investigation are illustrative of the fact that dumping has continued in spite of antidumping duty being in force.
    - ii) Chinese exporter cartels have established near monopoly in world markets for Vitamin C by fixing prices of Vitamin C intended for export.
    - iii) Chinese Vitamin C exports capturing the world markets because of low prices.
    - iv) Exporters in the subject country have capacities far in excess of domestic demand in home market and Indian demand.
    - v) The producers in the subject countries are exporting nearly 60-100% of the total production.
    - vi) The Indian market is highly price sensitive. Such being the case, availability of such low priced imports from subject country in the market is definitely causing an adverse impact on the domestic industry.
    - vii) Considering the export volumes from the subject country to third countries, exports to Indian market would increase in the event of revocation of anti dumping duty.
  - (e) Landed value of imports are at a price which is lower than the selling price of the Domestic Industry. The producers in the subject countries would, therefore, aggressively target Indian market in the event of cessation of anti dumping duty.
  - (f) The domestic industry is suffering injury in terms of price parameters. Further, aggravated injury cannot be ruled out if dumping continues and occurs in increased volumes in case present anti dumping duty is not extended.

**Submissions by the opposing interested parties**

95. The opposing interested parties have made the following submissions in this regard:
- i. The evidence provided by the applicant regarding huge surplus production capacities of Chinese producers does not specify whether the supply capacity is for exports or for domestic consumption. It also does not specify whether the supply capacity is aimed at India. In the absence of positive evidence, the claim of the applicant cannot be accepted.
  - ii. The applicant is not suffering any injury at present and further has failed to adduce ‘positive evidence’ to establish that there is a likelihood of recurrence of dumping or injury on expiry of the anti-dumping duty.
  - iii. The applicant has failed to provide any credible evidence to establish that the expiry of the duty would lead to a recurrence of injurious dumping. The applicant has submitted that there is a possibility of recurrence of injury based on the export orientation of Chinese exporters, the price attractiveness of the Indian market and the fact that producers in China have freely disposable capacities. It has been contended by the respondent that India is not a key market for exports from China. In particular, only 0.7% of the total exports of subject goods from China are exported to India.

**Examination by the Authority**

96. In order to determine whether the dumping is likely to continue or recur in the future if the duties are revoked; the trend in volume of sales of the exporter and its prices in the home market and third country export markets have been examined by the Authority. The submissions made by the domestic industry have also been considered.
97. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of antidumping duty is warranted. This also requires examination whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping. In the present investigation, there are continued dumped imports. Cessation of duty is likely to lead to continued dumping of the product. Considering the fact that the dumping margin in the previous investigations as well as the present investigation is significant and that there are favourable market conditions in the Indian market as far as demand and price for the subject goods are concerned, the Authority has reason to believe that dumping may intensify if the duty is revoked. It is a matter of fact that despite the anti-dumping measures in force, the subject country could still dump the subject goods in the Indian market.
98. The volume of dumped imports from China PR has remained significant over the injury period in spite of the fact that anti dumping duty on the subject goods is in force. The current volume of imports from the subject country itself is significant enough to show the likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.
99. As regards the argument concerning surplus capacities and potential exports to India, the Authority notes that the relevant consideration is existence of surplus capacities with the Chinese suppliers. These surplus capacities are required to be considered having regard to the domestic consumption of the product and any volumes committed by the Chinese producers in third countries markets. None of the Chinese producers has claimed that any of the exports made to third countries are under long term contract and capacities to this extent are not available with the Chinese producers.
100. As regards the argument that exports of the product from China to India constitutes only 0.7% of total exports from China to various countries globally, the Authority notes that the same at the least establishes significant possibilities of increased imports post cessation of anti dumping duty.
101. As regards the argument that anti dumping duty is in force for quite a long period and yet the domestic industry has claimed injury, the Authority notes that the present determination is based on actual verified information which clearly shows that the performance of the domestic industry has deteriorated significantly.
102. The Authority has examined the aspect of dumping and injury as well and holds that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the absence of anti dumping duty. The following analysis further shows the likelihood of continuation/intensification of dumping and injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duty:
- (i) **Level of current and past dumping margin**
103. The level of dumping margin in the original, previous sunset reviews as well as present investigation is significant. Despite the domestic industry holding significant capacity to meet the demand, the import of the subject goods from the subject country still continue at dumped prices. Given the level of price undercutting and price underselling, the volume of dumped import is likely to increase further in the event of revocation of anti-dumping duty.

**(ii) Price attractiveness of Indian market**

104.The price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of continuation and intensification of dumping. At the current landed price in India, there is positive price undercutting. Thus, with the cessation of anti dumping duty, the Indian prices would be too attractive for the Chinese producers to intensify their exports to India at dumped prices and there is strong likelihood that Indian consumers would resort to large scale imports of the subject goods from the subject country.

**(iii) Export orientation of producers in the subject country**

105.The domestic industry has contended that the Chinese producers/ exporters are highly export oriented. Considering the high demand and favourable market conditions for the subject goods in India and the high production capacity and export orientation of these producers, the Authority holds that in the event of revocation of anti dumping duties, these exporters are likely to increase their exports to India at dumped prices.

**(iv) Huge production capacity in the subject country**

106.The evidence provided by the domestic industry on the existing capacity in China shows that the capacities in China are far greater than the Indian demand for the subject goods. None of the Chinese producers has responded to the investigation. It is thus concluded that in the event of cessation of anti-dumping duty and considering the export orientation, the producers in China are capable of completely overtaking the Indian manufacturing sector engaged in the subject goods.

**(v) Dumping in third countries**

107.The evidence provided by the domestic industry shows existence of significant volume of exports to third countries at dumped prices. Cessation of anti dumping duty on imports of the subject goods would only lead to the likelihood of increased volume of dumped imports.

**(vi) Price undercutting, suppression, depression in the absence of measures**

108.The price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of the price at which the goods are likely to be exported from China in the event of cessation of anti dumping duty. As can be seen from the table below at the landed price in India, there is significant undercutting without anti dumping duty. Thus, with the cessation of anti-dumping duties, the Indian prices would be too attractive to these exporters and there is strong likelihood that Indian consumers would import substantially due to demand. The exporters would also be encouraged to channelize their output in the Indian market as they have excessive capacities and are selling their products at excessively low prices.

Particulars	Unit	POI
Net Sales Realization	Rs./kg	***
Cost of production	Rs./kg	***
Non injurious price	Rs./kg	***
Landed value of imports	Rs./kg	***
Price Undercutting	Rs./kg	***
Price underselling	Rs./kg	***
Profit/loss at import price	Rs./kg	***
Interest per unit	Rs./kg	***
Depreciation per unit	Rs./kg	***
PBIT	Rs./kg	***
Capital employed per unit	Rs./kg	***
Cash profit	Rs./kg	***

109. It is thus seen that should the present anti dumping duty be allowed to cease, performance of the domestic industry would decline materially in respect of price parameters. Further, should the domestic industry sell the product at import prices in the event of cessation of ADD, the domestic industry would suffer financial losses, negative return on investment and cash losses.

(vii) **Significant increase in volume of imports between original period and subsequent periods**

110. An analysis of the volume of imports reported in the previous cases as well as in the current period shows that volume of imports from China PR has remained significant despite existing anti dumping duties. When the imports have remained significant even in the presence of anti dumping duty, there are all the probabilities that the volume would increase in the event of cessation of anti dumping duty. There is no reason to believe that the volume of dumped imports will decline in the event of cessation of anti dumping duty.

(viii) **Market Share held by the subject country in the Indian market**

111. The market share of imports from China PR is quite significant in spite of the existing anti dumping duties. In the event of revocation of anti dumping duty, the volumes are bound to surge.

**Conclusion on Likelihood of dumping and injury**

112. Considering the current price of imports from the subject country, price difference between the domestic and imported product, price sensitiveness of the product, capacities with the responding exporter and other Chinese producers, dumping in third country markets, the Authority concludes that there exists clear likelihood of intensified dumping and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of anti dumping duty.

**Magnitude of Injury and injury margin**

113. The non-injurious price of the subject goods was determined by the Authority for the domestic industry, taking into account the cost data of the domestic industry. Since the product was subject to Drug Price Control Order during part period of the POI, the DPCO price fixed by the Government of India has been compared with the landed value of imports from the subject country for determination of the injury margin, which works out as follows:

**Injury Margin Table**

Injury Margins	UOM	Amount (Injury Margin as per NIP)	Amount (Injury Margin as per DPCO)
Landed Value	Rs./Kg	***	***
DPCO Price	Rs./Kg	-	***
NIP	Rs./Kg	***	-
Injury Margin	Rs./Kg	***	***
Injury Margin	US\$/Kg	***	***
Injury Margin %	%	***	***
Injury Margin	Range%	105-115	90-100

114. It is seen that injury margin is not only above de-minimis but also significant.

**I. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS**

(A) Post Disclosure comments of the opposing interested parties

115. The Authority notes that post Disclosure Statement submissions made by the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with in the Final Findings. The opposite interested parties have, in brief, filed the following post Disclosure Statement submissions:

- a. Anti dumping duty on imports of Vitamin C has been in existence for last 17 years and domestic producers are seeking an extension for further five years.
- b. Excessive confidentiality has been resorted to by the petitioner.

- c. There are serious quality related deficiencies in the coated grade of the product under consideration supplied by the Petitioner. The said grade of the product under consideration ought to be excluded from the scope of the investigation.
- d. There is a difference in the production process and technology adopted by the Chinese manufacturers and the domestic producers in India. Therefore, the methodology adopted for construction of normal value is flawed. Adjustments to the normal value to factor in higher input procurements costs incurred by Indian producers as a result of importing 2KGA rather than manufacturing it captively.
- e. There is lack of injury based on Economic Parameters relating to the Applicant as the Applicant's performance has improved significantly in terms of capacity, production, capacity utilization, sales, market share, inventory, productivity, wages, salaries and employment.
- f. There is clearly no price suppression or depression that can be attributed to imports of the subject goods. 2KGA constitutes 50 percent of the cost of production of Vitamin C. This is one of the reasons why the landed value of the imports from China is showing a decline over the corresponding period.
- g. The production process adopted by the Petitioner is different from the Chinese producers and is not cost-effective, leading to self-inflicted injury.
- h. The Authority ought to consider and balance the larger interest of the premix manufacturers so that the interests of the larger addition to the economy can be protected. Imposition of anti-dumping duty on subject for pharmaceutical purposes is not in public interest. In 2010, as a result of the imposition of anti-dumping duties on Vitamin C and fluctuations in raw material costs, manufacturers were forced to cease production of Vitamin C tablets.
- i. The extension of the ADD would result in making production of Vitamin C unviable – Vitamin C formulations are included in the National List of Essential Medicines.
- j. The removal of the maximum retail price for bulk drug manufacturers pursuant to the new DPCO order 2013 has resulted in increase in prices of the PUC by the applicant in the range of 10%-45%.
- k. The vitamin C imported for pharmaceutical use can be easily distinguished from Vitamin C imported for non-pharmaceutical use, as the exporters of Vitamin C for pharmaceutical use need to be registered with the Drug Controller General of India (DGCI) in India. In addition, even the importers of Vitamin C for pharmaceutical purposes would need to procure an Import License. Therefore, such an exemption, in addition to being required on public health grounds, is also feasible to implement.
- l. The Applicant should have provided injury related data for at least the domestic producers supporting the Application, which it claims taken together, constitute 88% of total domestic production.
- m. There has been a decrease in the volume of imports from the subject country over the course of the injury investigation period and the POI in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- n. The maximum selling price of Vitamin C has been regulated by the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) and any upward trend in prices of the domestic industry has been subject to a ceiling imposed by the NPPA.
- o. The profitability of the Applicant shows a decline, however, the decline is clearly attributable to significant increase in certain expenses incurred by the Applicant such as depreciation, wages and interest rather than imports of the subject goods.
- p. The reason for the decrease in the cash profits of the Applicant is due to an increase in investments. In particular, the Applicant appears to be incurring a gross profit but as a result of the increase in its investments, there has been a decline in its cash profits.
- q. The Applicant has failed to provide any credible evidence to establish that the expiry of the duty would lead to a recurrence of injurious dumping.
- r. India is not a key market for exports from China. Export orientation of Chinese producers is directed towards the US and EU and not towards India. Also, it may be looked into that China has near monopoly on World Vitamin C production does not come within the ambit of anti dumping laws.
- s. In particular, only 0.7% of the total exports of subject goods from China are exported to India. Existence of surplus production capacity of Chinese manufacturers cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury.
- t. The regulation of prices of finished formulations of Vitamin C in India by the NPPA makes India an unattractive market for exports of subject goods.

- u. There exists significant demand supply gap.
- v. Chinese manufacturers for the PUC are more competitive, a fact which has also been admitted by the Indian domestic manufacturers themselves.
- w. If the Chinese exporters wanted to capture the Indian market for Vitamin C by dumping the PUC, the Chinese exporters could have substantially increased the prices of the raw material 2KGA which would have resulted in bigger injury to the Indian bulk drug manufacturers of Vitamin C. It should be noted that in such circumstances, since there is no domestic manufacturer for 2 KGA in India, the option of initiating an AD investigation would also not be available.
- x. Grounds for using DGCI&S data instead of IBIS data as there no reasons to doubt the reliability of IBIS data.
- y. The veracity of the domestic industry's cost of production data which remained nearly the same despite a steep decline of 25% in 2KGA import prices as well as international corn prices. Data relating to the fall in 2KGA and corn prices.
- z. The impact of the NPPA price control on the like product which had a depressing effect on prices of the domestic industry.
- aa. Applicant is making gross profits, which has been exhibited by its data as well, and further is not facing any price suppression. Any fall in ROI and net profits is attributable to the increase in extraordinary expenses rather than allegedly dumped imports.
- bb. Normal value constructed based on cost of production in India is impermissible. The international raw material prices of 2 Keto L Gulonic Acid (2KGA), the main raw material, used in production of the subject goods should not form the basis of the Authority's normal value computation. Moreover, as 2KGA constitutes nearly 50% of the cost of production of the subject goods, the use of international prices of 2KGA would skew the normal value upwards.
- cc. The Authority must adjust the above input procurement costs and attendant costs relating to importation of 2KGA while constructing the normal value for China.
- dd. Level of past dumping margin is legally invalid.

**(B) Post Disclosure Comments of the Domestic Industry**

116. The Authority notes that most of the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry are repetitive in nature and have already been dealt with elsewhere in the Final Findings. Following are, in brief, the post Disclosure Statement submissions made by the domestic industry:

- a. The product under consideration in the present petition is Vitamin C. The scope of the product under consideration is the same as in the previous anti dumping investigations.
- b. The information on record clearly establishes that the production of the petitioner constitutes a major proportion in Indian production.
- c. The Authority has rightly proposed to treat all exporters in China as operating under non-market economy conditions as none of the exporters from China PR have responded or submitted Market Economy Treatment Questionnaire.
- d. Normal value has been determined considering constructed cost of production.
- e. The investigation has established existence of significant dumping.
- f. There have been significant imports of the product from the subject country in absolute terms in spite of anti dumping duty in force.
- g. Performance of the Domestic Industry in terms of production, capacity utilization, has improved in the current injury period. However, performance in terms of price parameters such as profits, return on investments, cash flow, etc. has deteriorated significantly and losses have been reported in 2012-13 and the POI.
- h. However, cessation of anti dumping duty shall have significant depressing effect on the prices of the domestic industry in the market.
- i. Both dumping margin and injury margin in the current POI are positive and significant.
- j. The price undercutting without prevailing anti dumping duties is positive and is quite significant.
- k. The import prices without anti-dumping duty are materially below selling price of the domestic industry. The consumers would, therefore, switch to imported product in the event of cessation of anti dumping duty which will lead to significant increase in imports of the product.

- l. There is likelihood of intensified imports in case existing anti dumping duty ceases.
- m. Non injurious price may be determined considering actual cost where fixed expenses are apportioned on the basis of production.
- n. The domestic industry is likely to suffer injury in the event of cessation of anti dumping duty.
- o. The anti dumping duty is required to be continued.
- p. Duty may be recommended on fixed amount basis in US\$ term.

**(C) Examination by the Authority**

117. The Authority notes that most of the post disclosure statement submissions made by the domestic industry and the opposing interested parties are repetitive in nature and have already been dealt with elsewhere in the Final Findings. Nonetheless, the Authority has addressed these issues to the extent considered relevant as under:

- a. As regards the argument that injury related data for all the domestic producers supporting the Application should have been provided, the Authority notes that the production of the petitioner alone constitutes 53% of the Indian production and in such a situation, there is no need to examine the data of the supporters for the purpose of determining standing of the petitioner as domestic industry.
- b. With regard to the contention raised by the anti dumping duty on Vitamin C has been in force for 17 years and should not be extended; the Authority holds that the Act and the Rules do not prescribe any time limit beyond which the anti dumping duty should not be extended. The legal provision clearly states that the anti dumping duty can be extended further from time to time, if it is found that the dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty. The investigation has shown that there is sufficient evidence of dumping and consequent injury and its likelihood.
- c. As regards the argument that the imposition of anti dumping duty shall be against public interest, the Authority notes that none of the interested parties has provided any information to establish that imposition of anti dumping duty shall have significant adverse effect on public at large. On the contrary, the domestic industry claimed that there has been no material adverse effect on the consumers because of anti dumping duty imposed in the past. The Authority also notes that the purpose of anti dumping duty is to address the unfair practice of dumping causing injury to the domestic industry.
- d. As regards the submissions of domestic industry and interested parties concerning low volume of imports and extension of anti dumping duty in such situations, the Authority considers that the issue is not relevant in the present case, as the volume of imports in the present case is quite significant.
- e. As regards applicability of DPCO, the Authority notes that the purpose of anti dumping duty is to provide level playing field to the producers of the product. It is also noted that the consumers have not established how continuation of anti dumping duty for another five years on Vitamin C would adversely prejudice the objective of making Vitamin C drug available at affordable prices and how manufacturing of drug formulations in India would become unviable. In any case, as per Price Drug Control Order of May, 2013, Vitamin C (bulk drug) is not covered under the DPCO order. It was covered before May, 2013.
- f. The petition was filed considering October 2012 to September 2013 as the investigation period. The Authority initiated the investigation considering October 2012 to December 2013 as the investigation period in order to allow the Authority to analyse and adopt data of most recent period. The petitioner has provided data for the POI fixed by the Authority and a copy of the same was placed in the public file, which was accessed by interested parties during the course of the proceedings.
- g. As regards confidentiality claims, the Authority has considered confidentiality claims made by parties and has allowed the same considering the confidentiality provisions under the law, the claims made by the domestic industry and past practices of the Authority. The Authority holds that the claims made by the domestic industry in this regard are consistent with the past practices of the Authority.
- h. As regards submissions concerning unacceptable quality and rejection of material, the Authority notes that the domestic industry has produced and supplied the product for all those applications where imported product has been used. The Authority also notes that preference of imported product over domestic product in view of alleged un-

quantified quality differences could not establish that the goods produced and supplied by the domestic industry are not like articles to the product under consideration.

- i. As regards the point that there is a difference in the production process and technology adopted by the Chinese manufacturers and the domestic producers in India and, therefore, the methodology adopted for construction of normal value is flawed, the Authority notes that the normal value has been constructed as per the practice adopted by the Authority in a large number of such investigations in the past.
- j. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is noted that there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, and the effect of such imports was to depress prices to a significant degree. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, the investigation has shown that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in terms of parameters such as profits, cash profits and return on investment. The investigation has thus shown that the domestic industry has continued to suffer injury.
- k. As regards the argument that the extension of the ADD would make Vitamin C formulations expensive, the Authority concludes that the investigation relates to imports of bulk drug and not formulations. Since Vitamin C is being dumped and causing injury, the scope of the investigation has been limited to Vitamin C to bring about fair trade practices in the imports of Vitamin C.
- l. As regards the argument that Vitamin C imported for pharmaceutical use can be easily distinguished from Vitamin C imported for non-pharmaceutical use, the Authority again concludes that the investigation relates to imports of bulk drug in all its forms and grades and the Authority's mandate is just to bring about fair trade practices in the imports of Vitamin C.
- m. As regards the submission that there no reasons to doubt the reliability of IBIS data, the Authority notes that the Authority always adopts the best available information in the absence of any response of the producers/exporters of the subject countries. Further, DGCI&S data has been taken by the Authority in a large number of investigations in the past where IBIS is also made available.
- n. The Authority further notes that Vitamin C (bulk drug) was covered under the DPCO order before May, 2013. Therefore, the injury margin should be the average of injury margin with relation to NIP and injury margin as per DPCO.
- o. As regards price behavior of imported finished product vis-a-vis imported raw material, it is correct that the prices of both have declined during the injury period, but the decline was more profound in the case of finished product aggravating injury to the domestic industry.

## I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

118. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the end user. The end user could still maintain two or even more sources of supply.

119. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not affect the availability of the product to the consumers.

## K. CONCLUSION

120. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in this final finding and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- a. There is continued dumping of the subject goods from the subject country and the dumping margin is above de-minimis and significant. Dumped imports are causing injury to the domestic industry in the period of investigation.
- b. Should the present anti-dumping duties cease, dumping of the subject goods from the subject country is likely to get intensified causing consequent injury to the domestic industry.

#### **L. RECOMMENDATIONS**

121. Having concluded as above, the Authority is of the view that the antidumping measure is required to be recommended to offset dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and its consequential injury to the domestic industry.
122. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, anti dumping duty equal to the amount indicated in the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, by the Central Government.

**DUTY TABLE**

S. No.	Heading/ Subheading	Description of goods	Forms/Grade (As per * Note below)	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit	Currency
1	29362700	Vitamin-C	All Forms/Grades	China PR	China PR	Any	Any	3.74	Kg	US\$
2	29362700	Vitamin-C	All Forms/Grades	China PR	Any other than China PR	Any	Any	3.74	Kg	US\$
3	29362700	Vitamin-C	All Forms/Grades	Any Other than China PR	China PR	Any	Any	3.74	Kg	US\$

*\*Note: The anti-dumping duty is applicable to all synonyms of Vitamin-C, including, most commonly used synonyms of Vitamin-C are ascorbic Acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone, etc., as described under entry number “867 of Merck Index”*

#### **M. FURTHER PROCEDURE**

123. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
124. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

J. K. DADOO, Designated Authority